फाल्गुन शुक्ल - 8 ■ संवत 2081 ■ वर्ष - 20 ■ अंक - 221 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » शुक्रवार » 07-03-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

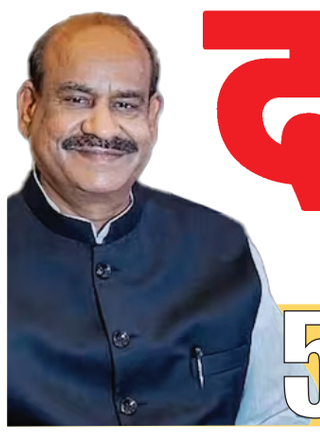

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाएंगे भारत के ऊर्जावान युवा : बिरला

6 सार्थक भागीदारी के बिना कैसे हल होंगे आधी दुनिया के मसले?

7 गोवा में महाराष्ट्र के लिए अविश्वसनीय नफरत : आयशा टाकिया

फर्स्ट टेक

यूक्रेन को खुफिया सैन्य जानकारी मुहैया करा रहा फ्रांस

पेरिस/एपी। अमेरिका द्वारा यूक्रेन के साथ खुफिया सूचना साझा करने पर रोक लगाने की घोषणा किए जाने के बाद फ्रांस इस युद्धग्रस्त यूरोपीय देश को खुफिया सैन्य जानकारी उपलब्ध करा रहा है। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू ने कहा, ''हमारी खुफिया जानकारी संप्रभु है। हमारे पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिसका लाभ हम यूक्रेन को दे रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि यूक्रेन को सभी सैन्य सहायता निलंबित करने के अमेरिकी फैसले के बाद, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनसे अमेरिकी सहायता की कमी की भरपाई के लिए ''विभिन्न फ्रांसीसी सहायता पैकेज में तेजी लाने'' के लिए कहा।

जेलेंस्की के गृहनगर में रूस ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल

कीव/एपी। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के गृहनगर में रात के समय एक होटल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी। जेलेंस्की ने कहा कि मध्य यूक्रेन के क्रीवी रीह में स्थित होटल पर हुए हमले से ठीक पहले यूक्रेनी, अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिकों सहित एक मानवीय संगठन के स्वयंसेवक अंदर घुसे थे। उन्होंने हालांकि नहीं बताया कि ये लोग उन 31 घायलों में शामिल थे या नहीं। यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर रातभर में 112 शाहिद और दो बैलिस्टिक इस्केंडर मिसाइलें दागीं।

दक्षिण कोरियाई लड़ाकू विमान ने गलती से बम गिराए, आठ लोग घायल

सियोल/एपी। दक्षिण कोरिया के दो लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी सेना के साथ बृहस्पतिवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान एक असैन्य क्षेत्र पर गलती से आठ बम गिरा दिए जिससे आठ लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वायु सेना ने एक बयान में बताया कि केएफ-16 लड़ाकू विमानों द्वारा गिराए गए एमके-82 बम 'फायरिंग रेंज' (बमबारी के लिए निर्धारित क्षेत्र) के बाहर गिरे, जिससे असैन्य क्षति हुई। वायुसेना ने कहा कि वह दुर्घटना के कारणों की जांच करने और आम नागरिकों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करेगी। उसने कहा कि लड़ाकू विमान अमेरिकी सेना के साथ एक दिवसीय गोलाबारी अभ्यास में हिस्सा ले रहे थे। एक वायुसेना अधिकारी ने स्थानीय पत्रकारों को बताया कि एक केएफ-16 के पायलट ने बमबारी स्थल के लिए गलत जानकारी डाल दी। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी पत्रकारों को बताया कि यह पता लगाने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है कि दूसरे केएफ-16 विमान ने भी असैन्य क्षेत्र पर बम क्यों गिराए।

07-03-2025 सूर्यास्त 6:29 बजे | 08-03-2025 सूर्योदय 6:31 बजे

BSE	NSE
74,340.09 (+609.87)	22,544.70 (+207.40)

सोना	चांदी
8,997 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	98,863 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

बिलबिलाहट

अब चला न जाए पीओके,
इस कारण ही बिलबिला रहा।
दहशतगर्दी को शह देकर,
केसर में कीचड़ मिला रहा।
अपना नंगापन ढँकने वो,
झूठा पायजामा सिला रहा।
जनता को देने बस गच्चा,
केवल झुनझुना हिला रहा।।

पाकिस्तान द्वारा 'चुराए गए हिस्से' की वापसी के बाद कश्मीर विवाद सुलझ जायेगा : जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर मुद्दे पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए दिया जवाब

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लंदन/इस्लामाबाद/भाषा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कश्मीर विवाद का समाधान ''कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी के बाद होगा, जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है।'' जयशंकर ने बुधवार को लंदन में चैथम हाउस थिंक-टैंक के एक सत्र को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

इस बीच पाकिस्तान ने कश्मीर के संबंध में जयशंकर की टिप्पणी को ''बेबुनियाद'' बताते हुए बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। साथ ही इस मुद्दे के समाधान की मांग की।

जयशंकर ने कश्मीर मुद्दे के ''समाधान'' के बारे में एक श्रोता के सवाल का जवाब देते हुए कहा था, ''कश्मीर के संबंध में, मुझे लगता है, वास्तव में हमने इसके ज्यादातर मुद्दों को हल करने की दिशा में अच्छा काम किया है।'' उन्होंने कहा, ''अनुच्छेद-370 को हटाना पहला कदम था, कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था तथा बहुत अधिक मतदान के साथ चुनाव कराना तीसरा कदम था।''

जयशंकर ने कहा, ''मुझे लगता है कि हम जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वह कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। जब ऐसा हो जाएगा, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर मुद्दे का समाधान हो जायेगा।''

पाकिस्तान ने जयशंकर की टिप्पणी को ''बेबुनियाद'' बताया

इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में जयशंकर की टिप्पणी को खारिज कर दिया।

खान ने कहा, ''आजाद जम्मू-कश्मीर के बारे में बेबुनियाद दावे करने के बजाय भारत को पिछले 77 वर्षों से अपने कब्जे में रखे गए जम्मू-कश्मीर के एक बड़े क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए।''

खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने जयशंकर के काफिले को बनाया निशाना

लंदन/नई दिल्ली/भाषा। लंदन में खालिस्तान समर्थक एक चरमपंथी ने उस समय सुरक्षा घेरा तोड़कर विदेश मंत्री एस जयशंकर की कार को रोकने का प्रयास किया जब वह थिंक टैंक 'चैथम हाउस' के मुख्यालय से बाहर निकल रहे थे। भारत ने ''अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह'' की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा की है। अलगाववादियों के झंडे लहरा रहे समूह को रोकने के लिए बुधवार रात को अवरोधक लगाए गए थे और बड़ी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों की उन पर नजर थी। तभी भारत का झंडा पकड़े एक व्यक्ति ने अवरोधकों को पार करके मंत्री की कार का रास्ता रोकने की कोशिश की और अधिकारी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारी उसे तुरंत एक तरफ ले गए। इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

सुरक्षा में चूक की इस घटना की भारत ने की निंदा

नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा में चूक की इस घटना की निंदा की और ब्रिटिश सरकार से ''अपने राजनयिक दायित्वों का पालन करने'' का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ''हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा संबंधी चूक की घटना के फुटेज देखे हैं।'' उन्होंने कहा, ''हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की, उकसावे वाली गतिविधियों की निंदा करते हैं।'' जायसवाल ने कहा, ''हम ऐसे तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जाने की निंदा करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे मामलों में मेजबान सरकार अपने कूटनीतिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करेगी।''

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उत्तरकाशी जिले में स्थित देवी गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुखसमृद्धि की कामना की ।

मोदी ने उत्तराखंड में बारहमासी पर्यटन की वकालत की

कहा : इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हरसिल (उत्तराखंड)/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में बारहमासी पर्यटन की पुरजोर वकालत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य में कोई 'ऑफ़ सीजन' नहीं होना चाहिए और हर सीजन 'ऑन सीज़न' रहे जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर मजबूती मिलेगी।

मुखबा में देवी गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल में पूजा-अर्चना करने के बाद हरसिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पर्यटक सर्दियों में प्रदेश में आएंगे तो उन्हें उत्तराखंड की वास्तविक आभा देखने को मिलेगी । मोदी ने राज्य में शीतकालीन पर्यटन के लिए गढ़वाली भाषा में एक नया शब्द 'घाम तापो पर्यटन' (धूप सेंको पर्यटन) गढ़ते हुए कहा, ''सर्दियों में जब देश के बड़े हिस्से में कोहरा छाया होता है, तो पहाड़ों पर धूप का आनंद होता है ।'' बारहमासी या 365 दिनों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साल भर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 'पर्यटन के 360-डिग्री दृष्टिकोण' की जरूरत है ।

भारत में अल्पसंख्यक हैं 'सबसे भाग्यशाली लोग': किरेन रीजीजू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में अल्पसंख्यक 'सबसे भाग्यशाली लोग' हैं, क्योंकि देश उनके लिए विशेष योजनाएं और कल्याण कार्यक्रम प्रदान करता है, जो दुनिया में कहीं और नहीं है।

रीजीजू ने यहां दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक और प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग यह गलत बयान दे रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, ''कुछ लोग यह झूठा विमर्श गढ़ रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। कुछ लोग यह संदेश फैलाते रहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन यह पूरी तरह से झूठ है।'' उन्होंने कहा, ''इसके विपरीत, भारत में अल्पसंख्यक सबसे भाग्यशाली लोग हैं क्योंकि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अन्य योजनाएं उपलब्ध हैं और उनके लिए अलग से योजनाएं और विशेष कार्यक्रम हैं। दुनिया में कहीं भी अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है।''

संसदीय कार्य मंत्री ने लोगों से राज्य और केंद्र दोनों की सरकारों की कल्याणकारी पहलों को सराहना करने की अपील की। उन्होंने कहा, ''हम भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं, इसलिए कृपया इसे याद रखें, अन्यथा हम सरकार के अच्छे कल्याणकारी कार्यों की सराहना नहीं कर पाएंगे, चाहे वे राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के।''

एसडीपीआई के खिलाफ ईडी ने देश भर में छापेमारी की

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआई) के राजनीतिक संगठन 'सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (एसडीपीआई) के खिलाफ धन शोधन मामले में जांच के तहत बृहस्पतिवार को देश भर में छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

संघीय जांच एजेंसी द्वारा एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. फैजी को तीन मार्च को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किए जाने के बाद यह छापेमारी की गई। फैजी वर्तमान में ईडी की हिरासत में है।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में निजामुद्दीन पश्चिम में एसडीपीआई मुख्यालय सहित दो स्थानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा, केरल में तिरुवनंतपुरम और मलप्पुरम, आंध्र प्रदेश में नांदयाल, झारखंड में पाकुड़, महाराष्ट्र में ठाणे, बेंगलूरु, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और जयपुर में छापेमारी की गई। ईडी ने फैजी (55) की गिरफ्तारी के बाद दावा किया था कि दोनों संगठनों के बीच एक ''संगठित'' संबंध है और पीएफआई राजनीतिक दल (एसडीपीआई) के माध्यम से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पीएफआई के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसे एक गैरकानूनी संगठन बताते हुए केंद्र सरकार ने सितंबर, 2022 में उसे प्रतिबंधित कर दिया था।

उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी

महाकुंभ में हमला कर भारत से भागना चाहता था बब्बर खालसा का आतंकी

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से बृहस्पतिवार तड़के गिरफ्तार किया गया बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) का आतंकी लजर मसीह महाकुंभ के दौरान अशांति फैलाकर भारत से फरार होना चाहता था। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने पत्रकारों को यह जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में बृहस्पतिवार तड़के कौशांबी जिले से बीकेआई के सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह को गिरफ्तार किया गया।

डीजीपी कुमार ने कहा कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इस आतंकी की गिरफ्तारी से पाकिस्तान से भारत में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी की पुष्टि भी हुई है।

लखनऊ के सिग्रेचर बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी कुमार ने कहा कि मसीह ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। उन्होंने कहा, हालांकि, धार्मिक आयोजन में कड़ी सुरक्षा जांच के कारण वह अपनी साजिश को अंजाम नहीं दे सका।

हनी सिंह के गाने के खिलाफ अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया

पटना/भाषा। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने गायक योयो हनी सिंह के हाल ही में रिलीज हुए गाने 'मैनियाक' में कथित अश्लीलता के खिलाफ शिकायत करते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका पर इस महीने के अंत में सुनवाई होगी। जनहित याचिका में सिंह और उनके साथ गाने में सहयोग करने वाले लोगों का नाम भी शामिल है, जिसमें गीतकार लियो ग्रेवाल और भोजपुरी गायक रागिनी विश्वकर्मा व अर्जुन अजनबी के नाम शामिल हैं। अभिनेत्री नीतू ने अदालत से प्रतिवादियों को 'गीत में संशोधन' करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी नीतू ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कुछ भोजपुरी और मैथिली फिल्मों का निर्माण भी किया है।

जय भिक्षु अर्हम् जय महाश्रमण

अनंत स्मृतियों का प्रथम वर्ष

स्व. श्रीमती पुष्पादेवी बरलोटा मुथा
धर्मपत्नी: श्री भूपेन्द्रकुमारजी मुथा, बेंगलोर (निम्बली-माण्डा)
(10.08.1958 - 07.03.2024)
सरलता, सौम्यता, सहजता, मिलनसारिता, मृदुभाषी, दया, करुणा, सहिष्णुता, परोपकारी, विनम्रता, दायित्व निष्ठ, संघ, संघपति के प्रति अटल, श्रद्धानत एवं संस्कारों की जननी श्रीमती पुष्पाबाई मुथा की स्मृति में उनके जीवन दर्शन पर आधारित
"दादी माँ एक स्मृति" पुस्तक विमोचन समारोह
दि. 09.03.2025, रविवार, प्रात: 10.30 बजे | स्थल : तेरापंथ भवन, गांधीनगर, बेंगलोर
सान्निध्य : युगप्रधान आचार्य श्री महाश्रमणजी की सुशिष्या साध्वी श्री संयमलताजी ठाणा ५
मुख्य अतिथि : श्री दिनेशजी गुंडुराव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, कर्नाटक सरकार
आप सभी स्नेही स्वजन, मित्रगण सादर आमंत्रित है।
दिन बीते, महिने बीते और बीत गया एक साल
बीच मझधार यूं छोड़ चली गई, हमेशा रहेगा हमें यह मलाल
आप आई नहीं पूछने हालचाल, इंतजार करते करते हो गए बेहाल
लौट आओं ना फिर से और कर दो हमको निहाल
श्रद्धाप्रणत : भूपेन्द्र मुथा (पति)
पुत्र-पुत्रवधु : नवनीत - मीना, संदीप - अनिता पौत्र-पौत्री : कुणाल, हार्दिक, निशा, दीक्षा
पुत्री-पुत्री जमाई : हेमलता - CA सुशील बाफना दौहित्री-दौहित्र : करिश्मा, नैतिक बाफना
ननद-ननदोई : सुशीलाबाई-स्व. मोतीलालजी धोका, सुशीलाबाई-उगमराज फुलफगर, कंचनबाई-रंगराज सुराणा, सुखीबाई-राजमल कुंकुलोल, चंद्राबाई-ज्ञानचंद ललवाणी, पुष्पाबाई-स्व. रमेशचंदजी सियाल
PRAKASH MEDICALS
Indiranagar, Bangalore - 560038. M : 9591040547, 9481884622

गंगा सफाई पर अपना वादा भूले मोदी : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/एजेन्सी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 साल पहले मां गंगा की सफाई के लिए 'नमामि गंगा योजना' शुरू कर वादा किया था कि वह गंगा को निर्मल बना देंगे लेकिन सच यह है कि इस अभियान के लिए आवंटित आधी राशि खर्च ही नहीं हुई और जो पैसा खर्च हुआ उससे गंगा साफ नहीं हुई।

खरगे ने प्रधानमंत्री की गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा, मोदी जी ने कहा था कि उनको 'माँ गंगा ने बुलाया है' पर सच ये है कि उन्होंने गंगा सफ़ाई की अपनी गारंटी को 'भुलाया' है। क़रीब 11 वर्ष पहले, 2014 में, नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। योजना में मार्च 2026 तक 42,500 करोड़ रुपए की राशि इस्तेमाल की जानी थी, पर संसद में गंगा से संबंधित सवालों के जवाब से पता चलता है कि दिसंबर 2024 तक केवल 19,271 करोड़ रुपये ख़र्च हुए हैं। यानी मोदी सरकार ने नमामि गंगे योजना के लिए आवंटित 55 प्रतिशत राशि ख़र्च ही नहीं की। आख़िर माँ गंगा के प्रति इतनी गहरी उदासीनता क्यों।

उन्होंने कहा, मोदी जी ने 2015 में हमारे एनआरआई साथियों से स्वच्छ गंगा निधि में योगदान देने का आग्रह किया था और मार्च 2024 तक इस फंड में 876 करोड़ रुपए दान दिए गए लेकिन इसका 56.7 प्रतिशत अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस फंड का 53 प्रतिशत सरकारी उपक्रमों से दान लिया गया है। नवंबर 2024 में राज्यसभा में सरकार ने बताया कि नमामि गंगे के 38 प्रतिशत प्रोजेक्ट्स अभी लंबित हैं। सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र बनाने के लिए कुल आवंटित फंड का 82 प्रतिशत ख़र्च किया जाना था, पर 39 प्रतिशत संयंत्र अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, और जो पूरे हुए हैं वो चालू ही नहीं हैं। उत्तर प्रदेश -75 प्रतिशत नाले जिन्हें संयंत्र में जाना था, उसका प्रदूषित पानी, सीधे गंगा जी में जा रहा है।

'भारतीय सहकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी की आवश्यकता'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को भारतीय सहकारी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी की आवश्यकता जताते हुए सहकारी संगठनों के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

सहकारी क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस बैठक में क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के माध्यम से परिवर्तन लाने वाले 'सहकार से समृद्धि' को बढ़ावा देने, सहकारी समितियों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना और सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहलों पर चर्चा की गई।

बैठक में सहकारिता मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय में सचिव आशीष कुमार भूटानी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास, प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बयान में कहा गया, ''प्रधानमंत्री ने भारतीय सहकारी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ

साझेदारी की आवश्यकता और सहकारी संगठनों के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।'' उन्होंने कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए निर्यात बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने और सहकारी समितियों के माध्यम से मृदा परीक्षण मॉडल विकसित करने का भी सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री ने वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए यूपीआई को रुपे केसीसी कार्ड के साथ एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला और सहकारी संगठनों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर जोर दिया।

बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी संगठनों की परिसंपत्तियों के दस्तावेजीकरण के महत्व पर भी जोर दिया।

उन्होंने सहकारी खेती को अधिक टिकाऊ कृषि मॉडल के रूप में बढ़ावा देने का सुझाव दिया और सहकारी क्षेत्र में कृषि और संबंधित गतिविधियों का विस्तार करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (एग्रीस्टैक) के उपयोग की सिफारिश की, जिससे किसानों को सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके।

निष्पक्षता से कर्तव्य निभाने का संकल्प लें सीआरपीएफ प्रशिक्षु अधिकारी: नायब सिंह सैनी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुरुग्राम/भाषा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के प्रशिक्षु अधिकारियों से आह्वान किया कि वे निष्पक्षता एवं निडरता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लें।

मुख्यमंत्री यहां स्थित प्रशिक्षण अकादमी में सीआरपीएफ के प्रशिक्षु अधिकारियों के 55वें बैच की 'पासिंग आउट परेड' में मुख्य अतिथि थे। दो महिला अधिकारियों समेत कुल 39 प्रशिक्षु अधिकारी बृहस्पतिवार को कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के बाद सीआरपीएफ अकादमी से उत्तीर्ण हुए। उन्होंने सीआरपीएफ के प्रशिक्षु अधिकारियों से आग्रह किया कि वे कानून और संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें, संवेदनशीलता के साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा करें तथा परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सत्य, ईमानदारी और समर्पण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहें। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्र सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये 39 प्रशिक्षु अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा सीआरपीएफ की गौरवशाली विरासत के अनुरूप राष्ट्र की अखंडता, एकता और संप्रभुता में योगदान देंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बल को देश की सुरक्षा की रीढ़ बताया।

मराठी मुंबई की भाषा! आरएसएस नेता जोशी के बयान पर विवाद के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि मराठी मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा है तथा यहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे सीखना और बोलना चाहिए।

फडणवीस ने यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सदस्य भास्कर जाधव द्वारा आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी की उस टिप्पणी पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि यह जरूरी नहीं कि मुंबई आने वाला व्यक्ति मराठी सीखे। जोशी ने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया है। मराठी मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा है।

विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) के नेताओं ने जोशी की टिप्पणी के खिलाफ मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि मराठी मुंबई की भाषा है। शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मांग की कि मराठी भाषा पर टिप्पणी के लिए जोशी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। फडणवीस ने कहा, ''मैंने भैयाजी की बात नहीं सुनी, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। हर किसी को मराठी सीखनी चाहिए और उसे बोलना चाहिए।'' उनकी सरकार अन्य भाषाओं का भी सम्मान करती है। फडणवीस ने कहा, ''अगर आप अपनी भाषा से प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो आप दूसरी भाषाओं के साथ भी ऐसा ही करें। मुझे यकीन है कि भैयाजी मेरी बात से सहमत होंगे।''

आरएसएस नेता जोशी पर राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए: उद्धव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठी भाषा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता सुरेश भैयाजी जोशी की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए मांग की कि उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने यहां विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए यह भी आरोप लगाया कि जोशी की टिप्पणी मुंबई को विभाजित करने के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के छिपे हुए एजेंडे को दर्शाती है।

जोशी ने बुधवार को यहां घाटकोपर इलाके में एक कार्यक्रम में कहा था, ''मुंबई में कोई एक भाषा नहीं है। मुंबई के हर हिस्से की अलग-अलग भाषा है। घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है। इसलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी पड़े।''

इस टिप्पणी की विपक्ष द्वारा कड़ी आलोचना किये जाने के बाद जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा था कि मराठी मुंबई की भाषा है और बाहर से आने वाले एवं अन्य भाषाएं बोलने वालों को भी इसे समझना चाहिए। जोशी ने कहा, ''मराठी मेरी मातृ भाषा है और मुझे इस पर गर्व है।'' जोशी ने साथ ही कहा कि घाटकोपर कार्यक्रम में की गई उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से समझा गया। ठाकरे ने जोशी पर निशाना साधते हुए कहा, ''उन्होंने (पिछले कुछ समय से) भारत-पाकिस्तान का मुद्दा नहीं उठाया है, लेकिन यह 'बटेंगे तो कटेंगे' का मुद्दा है। यह सिर्फ मराठी बनाम गैर-मराठी का मुद्दा नहीं है बल्कि मराठा बनाम गैर-मराठा और राज्य पर कब्जा करने का मुद्दा भी है।''

पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नारा लगाया था, ''बटेंगे तो कटेंगे।'' ठाकरे ने जोशी को गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में ऐसे बयान देने और सुरक्षित वापस आने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि 'मराठी मानुष' सभी का स्वागत करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी उस पर हमला कर सकता है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता ठाकरे ने कहा, ''भाजपा को मराठी मानुष की कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसे पता है कि वह उनके लिए वोट करेगा। यह परपीड़क मानसिकता है जो सामने आ गई है। यह मुंबई को तोड़ने की एक चाल है।''

व्यापारी, व्यवसाय मालिक खराब बुनियादी ढांचे के कारण संघर्ष कर रहे हैं : दिल्ली की मुख्यमंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि शहर भर के व्यापारियों और व्यवसाय मालिकों ने अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, खराब स्वच्छता और विकास की कमी पर निराशा व्यक्त की है और वे पिछली सरकार के कुप्रबंधन तथा अव्यवहारिक नीतियों से परेशान हैं।

आगामी दिल्ली बजट 2025-26 से संबंधित एक कार्यक्रम में गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार को व्यापारियों और उद्योगपतियों से बहुमूल्य सुझाव मिले हैं और उन्हें ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा, पिछले कई सालों से व्यापारी और व्यवसाय मालिक अव्यवहारिक नीतियों, नौकरशाही बाधाओं तथा पिछली सरकार की लापरवाही के कारण परेशान थे। कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ है - सड़कें और जल निकासी व्यवस्थाएं खराब स्थिति में हैं, और यहां तक कि प्रमुख बाजारों में शौचालय जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने चांदनी चौक, करोल बाग और लाजपत नगर जैसे छोटे और बड़े वाणिज्यिक केन्द्रों के समक्ष आ रही समस्याओं पर प्रकाश डाला, जो अपर्याप्त सीवर प्रणाली, सड़कों की खराब स्थिति और बुनियादी ढांचे की समग्र उपेक्षा से जूझ रहे हैं। पिछली आप सरकार की आलोचना करते हुए गुप्ता ने कहा कि उसने केवल समस्याओं का सार्वजनिक रूप से ढोल पीटने पर ध्यान केंद्रित किया था, हम समाधान खोजने और राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगामी बजट में राजधानी में व्यापारियों को समर्थन देने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता और व्यापार-अनुकूल नीतियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

एनआरआई और अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी में शामिल फर्जी कॉलसेंटर का हैदराबाद में भंडाफोड़

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (टीजीसीएसबी)ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी कि उसने हाई-टेक सिटी में फर्जी कॉल सेंटर के जरिये बड़े पैमाने पर हो रही साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है और मामले में 63 लोगों को गिरफ्तार किया है। करने की घोषणा की। टीजीसीएसबी की निदेशक शिखा गोयल के मुताबिक संदिग्ध लोग अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाली एक्सिटो सॉल्यूशंस नाम से संचालित फर्जी कॉल सेंटर में कार्यरत थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने फर्जी बीपीओ पर छापा मारा और साइबर अपराधों में उसकी संलिप्तता का खुलासा किया। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने फर्जी कॉल सेंटर के प्रबंध निदेशक और टेलीकॉलर (फोन से बात करने वाले)सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से महिलाओं के नौकरी के आवेदनों में उल्लेखनीय उछाल : रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से 2021 से 2024 के बीच महिलाओं की ओर से नौकरी के आवेदनों में तेज वृद्धि हुई है। पेशवर नेटवर्किंग मंच अपना.को ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

'अपना डॉट को' ने एक रिपोर्ट में कहा कि मंच ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में महिलाओं की ओर से नौकरी के आवेदनों में तीन गुना वृद्धि देखी, जो पिछले चार वर्षों में महानगरों से परे, महिला कार्यबल की भागीदारी में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से नौकरी के अवसरों के विस्तार, डिजिटल पहुंच में वृद्धि और नियोक्ताओं के भर्ती के बदलते तरीके से प्रेरित है। इससे गैर-महानगर क्षेत्रों की अधिक महिलाएं विविध उद्योगों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। रिपोर्ट वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के अंत तक 'अपना डॉट को' पर मौजूद आंकड़ों का विश्लेषण है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि बिक्री और कारोबार विकास, एडमिन और बैक ऑफिस, और ग्राहक सहायता दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में महिलाओं के लिए पसंदीदा नौकरी विकल्प के रूप में उभरे। नौकरी के कुल आवेदनों में से 55 प्रतिशत इन भूमिकाओं के लिए आए। इसमें कहा गया है कि दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में महिलाएं गैर-परंपरागत भूमिकाएं भी तलाश रही हैं, जिसमें वर्ष 2024 में फील्ड सेल्स में छह लाख आवेदन, डिलिवरी और लॉजिस्टिक्स में 2.5 लाख आवेदन और सुरक्षा सेवाओं में 1.5 लाख आवेदन हैं।

नए लोगों की भर्तियां बढ़ने से फरवरी में देश के रोजगार बाजार में 41% का उछाल : रिपोर्ट

मुंबई/भाषा। मुख्य रूप से नए लोगों (फ्रेशर्स) की भर्ती के कारण देश के रोजगार बाजार में फरवरी माह में भी तेजी जारी रही और इसमें सालाना आधार पर 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है।

एशिया के रोजगार एवं प्रतिभा मंच, फाउंडिट (पूर्व में मॉन्स्टर एपीएसी और एमई) के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में नए लोगों की नियुक्तियों में सालाना आधार पर 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह अपना करियर शुरू करने वाले प्रतिभाशाली कर्मियों के लिए नियोक्ताओं की निरंतर मांग को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी, 2025 में नियुक्तियों में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी नए लोगों की भर्तियों में उछाल के कारण हुई।

'मंदिरों के पैसे योजनाओं में': हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने भाजपा पर सांप्रदायीकरण करने का लगाया आरोप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिमला/भाषा। हिमाचल प्रदेश के मंत्री राजेश धर्माणी ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य द्वारा संचालित मंदिरों से प्राप्त धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में डाली जाती है तथा सामाजिक कार्यों और लोक कल्याण योजनाओं में उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन भाजपा इस मुद्दे का सांप्रदायीकरण कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। धर्माणी बचत भवन में मासिक बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1984 के तहत कार्यरत विभिन्न मंदिर न्यास परमार्थ गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए योगदान देते हैं। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस सरकार के फैसले को हिंदू विरोधी करार देते हुए कहा कि यह सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन छिपाने का प्रयास है। अधिसूचना में कहा गया है कि मंदिर न्यास मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में भी योगदान दे सकते हैं। धर्माणी ने कहा कि मंदिरों की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में डाली जाती है जिसका उपयोग सामाजिक कार्यों तथा जन कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है, लेकिन भाजपा इस मुद्दे का सांप्रदायीकरण कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस नेता धर्माणी ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा 'राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश की छवि खराब करने' की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पटवारी एवं कानूनगो मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि पटवारियों और कानूनगो के धरने और हड़ताल के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन राजस्व मंत्री इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

लोग अपनी जाति को लेकर संवेदनशील, पर दूसरों के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाते : अदालत

मुंबई/भाषा। बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने कहा है कि लोग आजकल अपनी जाति और समुदाय को लेकर तो संवेदनशील हैं, लेकिन दूसरी जातियों और समुदायों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते।

इसी के साथ उच्च न्यायालय ने डॉ. बीआर अंबेडकर के प्रति अनादर दिखाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया, जबकि मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति को सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ पोस्ट करने के लिए फटकार लगाई। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति संजय देशमुख की पीठ ने बुधवार को पारित आदेश में कहा कि हर सोशल मीडिया पोस्ट/टिप्पणी या भाषण पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता और ऐसी चीजों के प्रति असहमति या असंतोष जाहिर करने के विवेकशील तरीके भी हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता देवेंद्र पाटिल के खिलाफ अगस्त 2019 में छत्रपति संभाजीनगर जिले के दौलताबाद पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी और उसमें जारी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

प्राथमिकी में दावा किया था कि आरोपी ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए शिकायतकर्ता को फोन कर धमकाया था। आरोपी ने शिकायतकर्ता को कथित तौर पर अपशब्द कहे थे और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के प्रति अनादर भी दिखाया था। पीठ ने कहा आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत डॉ. अंबेडकर के प्रति कोई अनादर नहीं दर्शाती।

सरकार चिप डिजाइन को समर्थन देने पर कर रही विचार: आईटी सचिव कृष्णन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गांधीनगर/ भाषा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस कृष्णन ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के अगले चरण की रूपरेखा के साथ तैयार है और इसके क्रियान्वयन के लिए आंतरिक रूप से चर्चा चल रही है।

कृष्णन ने आईईएसए विजन शिखर सम्मेलन में कहा कि सरकार देश में महत्वाकांक्षी चिप डिजाइन परियोजनाओं के साथ-साथ सेमीकंडक्टर पैकेजिंग डिजाइन का बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ''भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण पर काम जारी है। हमने कई पक्षों के साथ चर्चा की है... कि कार्यक्रम को कैसे डिजाइन किया जाए। डिजाइन और रूपरेखा तैयार है, और सरकार में आंतरिक रूप से विस्तृत चर्चा चल रही है।'' कृष्णन ने डिजिटल माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि आईएसएम के दूसरे चरण में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए आवश्यक गैसों और अन्य तत्वों के लिए समर्थन प्रदान करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि आईएसएम के पहले चरण में कुल 76,000 करोड़ रुपए के व्यय का निर्धारण किया गया है। इसमें चिप विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयों के लिए 65,000 करोड़ रुपए, मोहाली में सेमीकंडक्टर लैब के आधुनिकीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए और डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

कृष्णन ने कहा, ''हमने वर्तमान में निर्माणाधीन पांच प्रमुख इकाइयों के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा, हमारे पास कुछ और परियोजनाएं हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है और उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।'' उन्होंने कहा कि फैबलेस परिवेश को और अधिक कुशलता से काम करने के लिए और अधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

जीएसटी परिषद ने आपदा उपकर की राज्यों की मांग पर विचार को मंत्री समूह का गठन किया

नई दिल्ली/भाषा। जीएसटी परिषद ने किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विशेष आपदा उपकर लगाने के लिए एकसमान नीतियां सुझाने को मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया है।

यह जीओम उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में गठित किया गया है। सात सदस्यीय मंत्री समूह प्राकृतिक आपदा के मामले में राजस्व जुटाने के लिए राज्यों द्वारा विशेष उपकर लगाने की संवैधानिक और कानूनी व्यवहार्यता की भी जांच करेगा। मंत्रियों का यह समूह इसकी भी पड़ताल करेगा कि क्या विशेष उपकर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होना चाहिए या इसे सभी क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ इसे बी2बी आपूर्ति या बी2सी आपूर्ति या दोनों पर लागू किए जाने की संभावना भी तलाशी जाएगी।

जीओएम के अन्य सदस्यों में असम (अजंता नियोग), छत्तीसगढ़ (ओ पी चौधरी), गुजरात (कनुभाई देसाई), केरल (के एन बालगोपाल), उत्तराखंड (प्रेमचंद अग्रवाल) और पश्चिम बंगाल (चंद्रिमा भट्टाचार्य) के वित्त मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा जीओएम उपकर की दर संरचना और समय अवधि की भी सिफारिश करेगा।

इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल, डेटा मंच एआई कोश की अश्विनी वैष्णव ने की शुरुआत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को 'इंडियाएआई कंप्यूट' पोर्टल और डेटासेट मंच 'एआईकोश' जैसी कई पहल की शुरुआत की जिनका उद्देश्य एआई तक पहुंच बढ़ाना और नवाचार को प्रोत्साहन देना है।

'इंडियाएआई मिशन' के एक साल पूरे होने के मौके पर वैष्णव ने इन पहल की शुरुआत की। कंप्यूट पोर्टल से छात्रों, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और सरकारी विभागों को 18,000 से अधिक जीपीयू, क्लाउड स्टोरेज और अन्य एआई सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। इस मंच का उद्देश्य एआई नवाचार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गैर-व्यक्तिगत डेटासेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना है। वैष्णव ने इस अवसर पर एआईकोश की भी शुरुआत की जो एक 'ऑल-इन-वन' डेटासेट मंच है जो संभावित विचारों को उद्योग समाधानों में बदलने में मदद करने के लिए संसाधन, उपकरण और विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है। ये डेटासेट मॉडल बिल्डर और डेवलपर के लिए उपलब्ध होंगे, ताकि वे भारत-विशिष्ट एआई मॉडल के साथ काम कर सकें और उन्हें पेश कर सकें।

वैष्णव ने कहा कि कंप्यूट पोर्टल का उपयोग भारत के अपने आधारभूत मॉडल को विकसित करने के लिए किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत के अपने आधारभूत मॉडल के लिए तैयारी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और इसके लिए कुल 67 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भारत के किफायती चंद्र अभियान का हवाला देते हुए कहा कि आधारभूत एआई मॉडल के लिए भी यही तरीका अपनाया जाएगा और भारत इसे अन्य देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर बनाएगा।

कर्नाटक मॉडल को सराहने वाला ऑक्सफोर्ड का ब्लॉग सीएमओ में काम कर चुके व्यक्ति ने लिखा था: भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कर्नाटक के विकास मॉडल की प्रशंसा करने वाला ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का ब्लॉग वास्तव में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यालय में काम कर चुके एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य द्वारा अद्वितीय रूप से तैयार किए गए कर्नाटक के विकास मॉडल का अर्थ है लोगों पर केंद्रित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शासन का निर्माण। उन्होंने कहा कि इस मॉडल का अध्ययन दुनिया भर के कई अर्थशास्त्रियों और विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है। गहलोत ने कहा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अपने मानवाधिकार हब ब्लॉग में इस मॉडल को 'अंधेरे में प्रकाश की तरह चमकने' और 'दुनिया के लिए ब्लू प्रिंट' के रूप में वर्णित किया है।

इस भाषण का जिक्र करते हुए अशोक ने सरकार पर राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल के पारंपरिक अभिभाषण में उनसे 'झूठ का पुलिंदा' बुलवाने का आरोप लगाया। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अशोक ने कहा, ये (ऑक्सफोर्ड ब्लॉग में कही गई बातें) 'अंधेरी रात' में लिखी गई लगती हैं। अशोक ने कहा कि वह इस दावे से हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि सरकार का मूल्यांकन किसने किया, किसने ऐसी रिपोर्ट लिखी और अर्थशास्त्री कौन है।

उन्होंने यह भी कहा कि लेख पर शोध करने पर पता चला कि ब्लॉग कुलपति या अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर द्वारा नहीं लिखा गया था। अशोक ने कहा कि ब्लॉग लिखने वाले का नाम विश्वविद्यालय की सूची से बिल्कुल भी नहीं है। अशोक ने दावा किया कि ऑक्सफोर्ड ह्यूमन राइट्स हब ब्लॉग कोई भी वकील, विधायक, समाज सुधारक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ लिख सकता है और शर्त बस इतनी है कि यह 500-700 शब्दों में होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ब्लॉग के लेखक जेहोश पॉल एक वकील हैं और उनके बायोडेटा में कहा गया है कि उन्होंने 2019 में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) और मंत्री प्रियांक खरगे के कार्यालय में काम किया था। उन्होंने कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा के कार्यालय में भी काम किया था।अशोक ने कहा, उन्होंने खुद कहा है कि वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री के मुख्य राजनीतिक सलाहकार (कैबिनेट रैंक) के पद पर काम कर चुके हैं। अगर ब्लॉग लिखने वाला व्यक्ति ऑक्सफोर्ड द्वारा नियुक्त होता और वह उसके वेतन पर होता, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। जब उन्होंने कर्नाटक मॉडल के बारे में 27 मार्च 2024 को ब्लॉग लिखा, तो वह वेतन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर रहे थे। भाजपा नेता ने कहा, आपके कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति, आपको विशिष्टता प्रदान करता है, ऐसा कोई भी कर सकता है। इसे पढ़ने के लिए राज्यपाल का उपयोग क्यों करें? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नाम का उपयोग क्यों करें?

तस्करी गिरोह से जुड़े रान्या राव के तार, मुख्य आरोपियों और विदेशी लिंक पर जांच केंद्रित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलुरु । कन्नड़ अभिनेत्री और आईपीएस अधिकारी की बेटी रान्या राव की गिरफ्तारी की जांच में पता चला कि वह सोने की तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थी और दुबई से बेंगलुरु तक सामान की तस्करी के लिए भारी कमीशन लेती थी। जांच में पता चला है कि रान्या राव सरगनाओं के इशारे पर सोने की तस्करी कर रही थी और अंतरराष्ट्रीय गिरोह का गठजोड़ बहुत गहरा था। सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री इतनी अमीर नहीं थी कि 17.29 करोड़ रुपये का सोना खरीद सके।

अधिकारियों ने पाया कि अभिनेत्री को दुबई से बेंगलुरु तक एक किलोग्राम सोने की तस्करी करने के लिए 4 लाख से 5 लाख रुपये का कमीशन मिला था। सरगनाओं ने उसे सोने की तस्करी में शामिल किया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह एक सेवारत आईपीएस अधिकारी की बेटी है और इसका फायदा उठाकर तस्करी को अंजाम दे सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों को इसमें बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कर्मचारियों की संलिप्तता का भी संदेह है। जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि रान्या राव ने सोना किसे सौंपा। अधिकारी रान्या राव के बैंक खातों से डाटा एकत्र कर रहे हैं और पिछले दो वर्षों के लेन-देन का विश्लेषण कर रहे हैं। उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और नेटवर्क के बारे में सुराग पाने के लिए फोन से जानकारी एकत्र की जा रही है।

इस बीच, सूत्रों ने बताया कि रान्या राव से हवाई अड्डे और उसके आवास से भारी मात्रा में सोना और नकदी जब्त होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले को अपने हाथ में ले सकता है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारी उनके आवास से जब्त की गई 2.67 करोड़ रुपये की कथित नकदी की जानकारी ईडी के साथ साझा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राव पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भी आरोप लग सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि रान्या राव ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में सहयोग नहीं किया और अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि वह डीजीपी की बेटी है। अधिकारियों को उस पर शक हुआ और उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए डीआरआई को सक्रिय किया गया। इस बीच, कथित तौर पर उसे हवाई अड्डे से बाहर ले जाने वाले पुलिसकर्मी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। डीआरआई के अधिकारियों ने सोमवार रात बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री से 14.8 किलोग्राम सोना जब्त करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट से आने के बाद अभिनेत्री को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। डीआरआई के अधिकारी उसकी दुबई की लगातार यात्राओं के बाद उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे।

विवाह के बंधन में बंधे भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और गायिका शिवश्री स्कंदप्रसाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु दक्षिण सीट से सांसद व भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत गायिका शिवश्री स्कंदप्रसाद बृहस्पतिवार को विवाह के बंधन में बंध गये। विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पारंपरिक तरीके से सम्पन्न हुआ। पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना और अर्जुन राम मेघवाल सहित भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के साथ-साथ पार्टी के कई सांसद और विधायक भी समारोह में शामिल हुए। आला नेताओं ने तेजस्वी और शिवश्री को आशीर्वाद भी दिया। इस साल की शुरुआत में कई खबरों में यह जानकारी दी गयी थी कि सूर्या, शिवश्री से विवाह करेंगे। शिवश्री ने बायोइंजीनियरिंग में स्नातक और चेन्नई संस्कृत कॉलेज से परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वह एक भरतनाट्यम नृत्यांगना भी हैं। हाल ही में 34 वर्षीय सांसद तेजस्वी और शिवश्री आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के आश्रम गये थे और उनका आशीर्वाद लिया था।

एसडीपीआई कार्यालयों पर ईडी के छापे: रीजीजू ने कहा- तथ्यों एवं आंकड़ों पर कार्रवाई करती हैं एजेंसियां

तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने एसडीपीआई कार्यालयों पर ईडी की छापेमारी का बृहस्पतिवार को बचाव करते हुए कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों की सभी कार्रवाई कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होती हैं।

रीजीजू पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उनसे प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित राजनीतिक संगठन एसडीपीआई के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी को लेकर सवाल पूछा गया था जसके जवाब में उन्होंने कहा, प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई सभी कार्रवाई कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होती हैं, जिन पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। वह दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक और प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने के लिए तिरुवनंतपुरम में थे।

भाषाई समानता की मांग करना अंधराष्ट्रवादी होना नहीं है : स्टालिन

चेन्नइ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि भाषाई समानता की मांग करना अंधराष्ट्रवादी होना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि असली अंधराष्ट्रवादी और राष्ट्रविरोधी, हिंदी कट्टरपंथी हैं जो मानते हैं कि उनका अधिकार स्वाभाविक है लेकिन विरोध देशद्रोह है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, जब आप विशेषाधिकार के आदी हो जाते हैं तो समानता उत्पीड़न जैसी लगती है। मुझे याद है जब कुछ कट्टरपंथियों ने हमें तमिलनाडु में तमिलों के उचित स्थान की मांग करने के 'अपराध' के लिए अंधराष्ट्रवादी और राष्ट्रविरोधी करार दिया। उन्होंने कहा, गोडसे की विचारधारा का महिमामंडन करने वाले लोग उस द्रमुक और उसकी सरकार की देशभक्ति पर सवाल उठाने का दुस्साहस करते हैं, जिसने चीनी आक्रमण, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और करगिल युद्ध के दौरान

सबसे अधिक धनराशि का योगदान दिया, जबकि उनके वैचारिक पूर्वज वही हैं जिन्होंने 'बापू' गांधी की हत्या की थी।

साथ ही उन्होंने कहा, भाषाई समानता की मांग करना अंधराष्ट्रवाद नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अंधराष्ट्रवाद क्या होता है? अंधराष्ट्रवाद 140 करोड़ नागरिकों पर लागू होने वाले तीन आपराधिक कानूनों को एक ऐसी भाषा देना है जिसे तमिल लोग न बोल सकते हैं और न ही पढ़कर समझ सकते हैं। अंधराष्ट्रवाद उस राज्य के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करना है जो देश में सबसे अधिक योगदान देता है और 'एनईपी' नामक जहर को निगलने से इनकार करने पर उसे उचित हिस्सा देने से मना किया जाता है। उन्होंने कहा, किसी भी चीज को थोपने से दुश्मनी पैदा होती है, दुश्मनी एकता को खतरे में डालती है। इसलिए, असली अंधराष्ट्रवादी और राष्ट्रविरोधी, हिंदी के कट्टरपंथी हैं जो मानते हैं कि उनका हक स्वाभाविक है लेकिन हमारा विरोध देशद्रोह है।

इसके अलावा, हिंदी थोपे जाने की आलोचना करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग धर्म से तो एकजुट हैं, लेकिन भाषा से अलग हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश के लोगों पर भाषा थोपना नए देश के निर्माण का मूल कारण था। भाषा का प्रभुत्व तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से एक था। उन्होंने आगे कहा कि मातृभाषा मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है और इसे छूना खतरनाक होगा। जब किसी भाषा को जबरन थोपा जाता है तो इससे दुश्मनी ही बढ़ती है और देश की एकता पर असर पड़ता है।

स्टालिन ने कहा, अपनी मातृभाषा की तरह हम दूसरों की मातृभाषा का भी सम्मान करते हैं और जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी है, वे भी हमारे भाई-बहन हैं। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि केंद्र सरकार ने 'हिंदी दिवस' मनाया, जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध अन्य भाषाओं के लिए अलग से कोई उत्सव क्यों नहीं मनाया गया।

प्रदर्शन

राज्य एससी एसटी एसोसिएशन के सदस्यों ने गुरुवार को भाजपा नेताओं बीवाई विजयेंद्र, चालावाडी नारायणस्वामी के साथ मिलकर एससी एसटी फंड के अन्य योजनाओं के लिए दुरुपयोग के खिलाफ बेंगलूरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया।

लोकायुक्त टीम ने गुरुवार को टुमकुरु में चिकित्सा अधिकारी डॉ. जगदीश के घर पर छापा मारा।

लोकायुक्त ने कर्नाटक में आठ सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे

लोकायुक्त सूत्रों ने बताया कि उन्होंने नकदी, गहने, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और रियल एस्टेट तथा विभिन्न बांड में उनके निवेश से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। लोकायुक्त के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में आठ सरकारी अधिकारियों से संबंधित परिसरों पर छापे मारे, जिन पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार, छापे बेंगलूरु, कोलार, तुमकुरु, कलबुर्गी, विजयपुरा, दावणगेरे और बागलकोट जिलों में मारे गए। जिन अधिकारियों के यहां छापेमारी की गई उनमें बेंगलूरु में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में 'ग्रुप ए' के तहत मुख्य अभियंता टी. डी. नंजुंदप्पा, बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका में गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन, राजमार्ग इंजीनियरिंग 'ग्रेड-1' के कार्यकारी अभियंता एच. बी. कलेशप्पा, कोलार में सहायक कार्यकारी अभियंता जी. नागराज, कलबुर्गी में परियोजना कार्यान्वयन इकाई के जगन्नाथ, दावणगेरे में स्वास्थ्य विभाग में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता इकाई के जिला सांख्यिकी अधिकारी जी. एस. नागराजू शामिल हैं।

जिन अन्य अधिकारियों के यहां छापेमारी की गई उनमें उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तवरकेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तुमकुरु के डॉ. पी. जगदीश; पंचायत राज इंजीनियरिंग विभाग, बागलकोट में प्रथम श्रेणी सहायक (एफडीए) मलप्पा सबन्ना दुर्गादा और एफडीए, हाउसिंग बोर्ड, विजयपुरा में शिवानंद शिव शंकर केंभवी शामिल हैं। लोकायुक्त सूत्रों ने बताया कि उन्होंने नकदी, गहने, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और रियल एस्टेट तथा विभिन्न बांड में उनके निवेश से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं।

राष्ट्रवादी नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है कांग्रेस : सीटी रवि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भाजपा नेता सी.टी. रवि ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा कि वह राष्ट्रवादी पार्टी नहीं, बल्कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। सी.टी. रवि ने मैसूरु के उदयगिरि थाने के बाहर मंगलवार को हुए हमले के संदर्भ में आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार हमलावरों को बचाने की कोशिश कर रही है। यह सब कुछ इसलिए हुआ है, क्योंकि कांग्रेस कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने घुसपैठियों के संदर्भ में कहा कि हमें इसे किसी पार्टी विशेष से जुड़े मुद्दे के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसे देश के खतरे के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह देश की सुरक्षा-व्यवस्था के लिए खतरा है।

उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानियों के अलावा बांग्लादेशी भी बड़ी संख्या में यहां घुसपैठिए बनकर रह रहे हैं। ऐसे में इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो आगामी दिनों में हमारे लिए चुनौती पैदा हो जाएगी। इससे देश को खतरा पैदा हो जाएगा। यह राजनीति से नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा।

उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार हर चीज की कीमत दोगुनी कर चुकी है। प्रदेश में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जिससे यहां के लोगों का जीना दुभर हो चुका है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में सभी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं जिससे आम जनता का जीना मुहाल हो चुका है।

उन्होंने कहा, राज्य सरकार चाहे तो ऑक्सीजन के दाम भी बढ़ा दे। इसके बाद प्रदेश में लोगों को सांस लेने के लिए भी शुल्क अदा करना होगा। लेकिन, राहत की बात यह है कि यह सरकार के बस में नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के बस में हो, तो वह ऑक्सीजन पर भी शुल्क लगा चुकी होती।

भाजपा नेता ने कहा कि प्रदेश में लोग इस सरकार की कार्यशैली से त्रस्त हो चुके हैं। अब इस सरकार को अपनी कार्य संस्कृति बदलनी होगी और लोगों के हितों को तवज्जो देना होगा। लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार इस दिशा में किसी भी प्रकार का कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। उन्होंने तमिलनाडु में जारी भाषा विवाद पर कहा कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही देश में त्रिभाषा प्रणाली लागू है। कुछ लोग राजनीति करने की ताक में बैठे रहते हैं। हम सभी ने देखा कि किस तरह से भाषा के नाम पर लोगों को तमिलनाडु में भड़काया गया। उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण मिलने के संदर्भ में कहा कि ऐसी बातें करने वाले गैर संवैधानिक राजनीतिक दल हैं, क्योंकि डॉ. अंबेडकर संविधान में स्पष्ट कर चुके हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

बागड़े ने सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का किया आह्वान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने क्षेत्रीय विकास एवं सामुदायिक उत्थान की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश देते हुये केंद्र एवं राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को जरूरतमन्दों तक पहुंचाकर खुशहाली लाने के लिए समर्पित होकर प्रयास करने का आह्वान किया है। बागड़े ने गुरुवार को जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह आह्वान किया। बैठक में पीपीटी के माध्यम से जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी गयी।

उन्होंने बैठक में केन्द्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन प्रगति एवं प्राप्त उपलब्धियों, भौगोलिक परिस्थितियों एवं संसाधनों की कमी से प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार के लिए योजना एवं कार्यक्रम, स्थानीय नागारिकों के पलायन को रोके जाने के लिए किये जा रहे प्रयास तथा हिन्दू विस्थापितों की स्थिति एवं सुरक्षा पर्यवेक्षण सहित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और सम सामयिक हालातों पर जानकारी ली।

बागड़े ने इस दौरान विशेषकर मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वामित्व योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल ग्रहण घटक), पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) आदि की समीक्षा करते इनसे अधिकाधिक लोगों को लाभांवित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उद्यान विभाग की योजनाओं नेशनल हेल्थ मिशन, यूनिसर्वल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री खनन क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना.जीवन ज्योति बीमा योजना, ई-नाम परियोजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित विभिन्न केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की बिन्दुवार विस्तार से समीक्षा की और इनमें लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति के निर्देश दिये।

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, कार्यवाही स्थगित

जयपुर। राजस्थान में खराब कानून-व्यवस्था को लेकर बृहस्पतिवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी के कारण सदन की कार्रवाई लगभग आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जेल में बंद अपराधी व गैंगस्टर बाहर के लोगों से फिरौती वसूल करने की साजिश रच रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं। शर्मा ने कहा कि इस तरह के एक मामले में एक व्यापारी ने सुरक्षा के लिए जिला पुलिस अधीक्षक से गुहार लगायी और सुरक्षा देने के बदले उसे 76 लाख 17 हजार रुपये का बिल भेजा गया। विधानसभा में जूली ने इसे गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि भरतपुर से सांसद ने पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और वीडियो जारी किया। विधानसभा अध्यक्ष ने जूली को इस मामले पर बोलने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया और कुछ देर हंगामे व नारेबाजी के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही लगभग आधे घंटे के लिए एक बजे तक स्थगित कर दी।

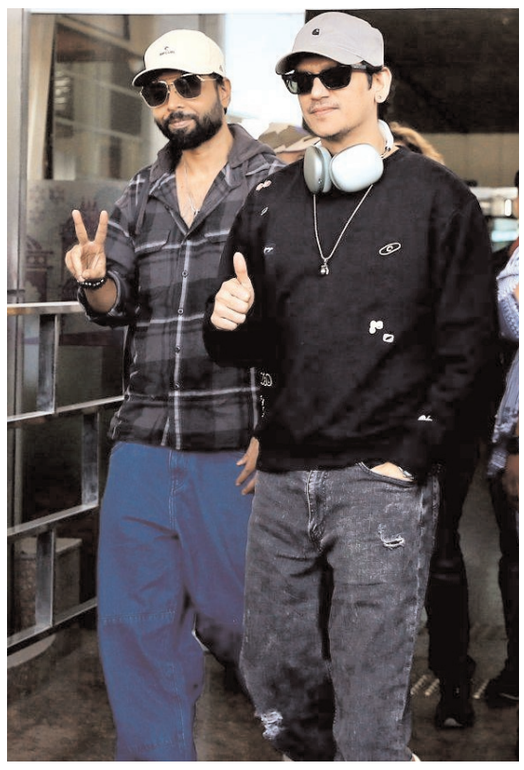

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बनर्जी और विजय वर्मा गुरुवार को जयपुर में आईफा अवार्ड 2025 में भाग लेने के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे।

दीया कुमारी को वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से किया सम्मानित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। पेसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दीया कुमारी को वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया हैं। उन्हें यह सम्मान आईटीबी बर्लिन, जर्मनी में सेशेल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री, डॉ. एलन सेंटएन्ज द्वारा दिया गया। उप मुख्यमंत्री की ओर से पर्यटन विभाग के अधिकारी, अपर निदेशक आनंद त्रिपाठी, उप निदेशक पर्यटन उपेन्द्र सिंह शेखावत ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। राजस्थान सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्कर्ष कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलकर राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा देश और दुनिया के विभिन्न पर्यटन मंचों पर राजस्थान के पर्यटन की ब्रांडिंग की जा रही है। इसी के तहत पेसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स संगठन (पटवा) ने राजस्थान ने को यह सम्मान प्रदान किया हैं।

पुलिस ने ब्यावर ब्लैकमेल मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के ब्यावर जिले में यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले की विस्तृत जांच के लिए पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने पूरे मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेम सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेम सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया, बिजयनगर मामले को लेकर बुधवार देर रात एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मामले की गहन जांच की जाएगी और जो भी साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्यावर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मामले की विस्तृत जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे। वहीं इस मामले को लेकर बुधवार को स्कूली छात्राओं ने पुष्कर में रैली निकाली और ब्रह्मा मंदिर में भगवान को संबोधित ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर मामले का विरोध किया और नारे लिखी तख्तियां लेकर आरोपियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस मामले में एक और आरोपी को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी, लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें दूसरे आरोपियों से मिलवाता था। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने पीड़िता के परिवार के सदस्यों की शिकायतों के आधार पर 16 फरवरी को तीन प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में नौ मुस्लिम और दो हिंदू लड़के शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिये गये तीन नाबालिग भी मुस्लिम हैं। ब्यावर जिले में मुस्लिम आरोपियों ने पांच नाबालिग हिंदू लड़कियों का कथित तौर पर यौन शोषण कर उन्हें ब्लैकमेल किया। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित लड़कियों के परिजनों की ओर से मिली शिकायतों पर 16 फरवरी को तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों में नौ मुस्लिम और दो हिंदू हैं। हिंदू लड़के कैफे संचालक हैं। ये मामले ब्यावर के बिजयनगर थाने में दर्ज किए गए थे। अधिकारी ने बताया कि मामला तब सामने आया जब पीड़ित नाबालिग लड़कियों में से एक ने आरोपी को देने के लिए अपने पिता के बटुए से 2,000 रुपये चुराए।

उन्होंने बताया कि लड़की के पास से एक चीनी मोबाइल फोन भी बरामद किया गया, जिससे वह कथित तौर पर आरोपी से बात कर रही थी। अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद आरोपियों के परिवारों, स्थानीय जामा मस्जिद और एक सौ साल पुराने कब्रिस्तान को बिजयनगर नगर पालिका प्रशासन से अतिक्रमण संबंधी नोटिस मिले। उन्होंने बताया कि कुछ अतिक्रमण पहले ही हटा दिए गए हैं।

सड़क हादसे में छह लोगों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के आबू रोड इलाके में बृहस्पतिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई व एक महिला घायल हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह हादसा सिरोही के किवरली गांव के पास तड़के लगभग तीन बजे तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ट्रॉले से टकरा गई।

माउंट आबू के क्षेत्राधिकारी गोमाराम ने बताया कि कार में सवार लोग जालोर जिले के एक गांव के रहने वाले थे और अहमदाबाद से लौट रहे थे। किवरली के पास कार ट्रोले में घुस गई।

उन्होंने बताया कि कार में सवार चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि दो की मौत अस्पताल में हुई। गोमाराम ने बताया कि एक महिला का इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान नारायण प्रजापत, उनकी पत्नी पोशी देवी और बेटे दुष्यंत, चालक कालूराम, उनके बेटे यशराम और जयदीप के रूप में हुई है।

उदयपुर के सज्जनगढ़ वन क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाने के प्रयास जारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के उदयपुर में सज्जनगढ़ वन क्षेत्र में लगी आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया हालांकि आग पर काबू पाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उदयपुर के जिलाधिकारी नमित मेहता ने पत्रकारों को बताया कि हालात पर काबू पाने के लिए दमकल की 14 गाड़ियां लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि तेज हवाओं के कारण आग ने बृहस्पतिवार एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया हालांकि आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस, दमकल और वन विभाग की टीमें भी हालात पर नजर रख रही हैं लेकिन अब तक हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं जताई गयी है। पुलिस के अनुसार, जिस स्थान पर आग लगी उसके आसपास आबादी वाला क्षेत्र है हालांकि प्रशासन ने कुछ घरों को खाली करा दिया है और उन घरों से गैस सिलेंडर निकाल लिए गये हैं। पुलिस ने बताया कि आग के मद्देनजर सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और बायोलॉजिकल पार्क दोनों में पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया गया है।

वन अधिकारी (डीएफओ) सुनील सिंह ने बताया कि आज (बृहस्पतिवार को) आग फैलने की सूचना मिली थी और उस समय मानसून पैलेस व बायोलॉजिकल पार्क में करीब 50 पर्यटक मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले टिकट खिड़की को बंद किया गया और उसके बाद सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया तथा पार्क में प्रवेश बंद कर दिया गया।

पुनः उद्घाटन की परंपरा नहीं डाली जानी चाहिए : गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में निर्मित संविधान क्लब के आठ मार्च को होने वाले शुभारंभ पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जब इस क्लब का पहले उद्घाटन हो चुका है तो अब इसका वापस उद्घाटन की परंपरा क्यों डाली जा रही हैं। गहलोत ने गुरुवार को यहां संविधान क्लब के उद्घाटन को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि यह स्थिति अच्छी नहीं हैं और अभी भी समय है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खुद ही ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष बहुत बड़ा गरिमामय पद है और उनको शायद जानकारी दी गई कि नहीं दी गई कि इसका उद्घाटन हो चुका है। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष डा सी पी जोशी, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और स्वायत शासन मंत्री शांति धारीवाल सब कार्यक्रम में मौजूद थे। अखबारों में फोटो छप गए तो सबको मालूम है कि यह उद्घाटन हो चुका है और ऐसी परंपरा क्यों डाल रहे हैं कि वापस उसका उद्घाटन करवाओ, शुभारंभ के नाम पर बुलाते हैं।

उन्होंने कहा इसी प्रकार याद होगा कि पांच-छह साल पहले वसुंधराजी ने बुलाया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को, रिफाइनरी का प्रोजेक्ट जो 37 हजार करोड़ का था, जब मैंने उसका शिलान्यास कराया था, श्रीमती सोनिया गांधी आईं थीं, और वो टाइम बाउंड प्रोग्राम पूरा हो जाता, पांच साल तक उसको बंद रखा गया कि श्रेय कांग्रेस को नहीं मिले, सिर्फ इसलिए कि श्रेय नहीं मिले। उन्होंने कहा कि कंस्टीट्यूशन क्लब प्रोजेक्ट को इसलिए बंद रखा गया कि श्रेय कांग्रेस को नहीं मिले। गांधी वाटिका को भी एक साल

इसलिए बंद रखा गया कांग्रेस को श्रेय नहीं मिले।

गहलोत ने कहा यह इनकी सोच बहुत ही निम्न स्तर की है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो स्थिति बनी है वो जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट पांच साल बंद रखा गया फिर शुभारंभ के नाम पर बुलाया गया मोदीजी को, आज तक पूरा नहीं हुआ है बल्कि 37 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग अब एक लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है ,कहते हैं 80 प्रतिशत के आसपास काम पूरा हुआ है। तो कोई डिले हो गया प्रोजेक्ट तो उसका कॉस्ट बढ़ेगी, एस्केलेशन होगा, पब्लिक इंटरेस्ट वो कभी नहीं होता है। हमनें कोई प्रोजेक्ट को जो बीजेपी राज में शुरू हुए हैं इंक्लूडिंग ईआरसीपी जो वसुंधराजी ने शुरू की थी हमनें कोई प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि हमारी सोच में और उनकी सोच में इतना रात दिन का फर्क है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां यह सरकार और यहां के विधानसभा अध्यक्ष पता नहीं क्या सोच करके इसका वापस शुभारंभ करने के नाम पर एक साल तक बंद रखा गया, जो उद्देश्य से बनाया गया है कंस्टीट्यूशन क्लब, हिंदुस्तान में सबसे शानदार कंस्टीट्यूशन क्लब राजस्थान में बना है,और राज्यों में तो होगा भी नहीं, खाली दिल्ली के अंदर लोकसभा, पार्लियामेंट के साथ अटैच्ड एक कंस्टीट्यूशन क्लब।

'वहम की दवा हकीम के पास भी नहीं', स्टालिन के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वहम की दवा हकीम के पास भी नहीं है। कुछ लोग इस तरह के बहन से पॉलिटिकल लाभ पाने की कोशिश करते हैं। अब देखने वाली बात है कि स्टालिन कौन से ब्रैकेट में खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे हैं। शेखावत शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय और अमानत की शादी में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 30 साल तक के लिए 1971 की जनगणना को ही परिसीमन का आधार बनाया जाए। स्टालिन को आशंका है कि परिसीमन से लोकसभा में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा। इस बहस की प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत में जोधपुर में दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान एप्लरशन बेस हैं। वहम की दवा हकीम के पास भी नहीं है। कुछ लोग इस तरह के बहन से पॉलिटिकल लाभ पाने की कोशिश करते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी से जुड़े एक सवाल के जवाब में शेखावत ने कहा कि बाहर से आकर जो भी व्यक्ति जोधपुर में या राजस्थान में आकर शादी करते हैं उसे विवाह समारोह में आने वाले लोगों के चलते हुए हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और शहर की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा लाभ होता है। मैरिज इवेंट्स और सेरेमनी ये आज की दुनिया में टूरिज्म का एक नया वर्टिकल बनकर खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसी हैवीवेट वेडिंग का जोधपुर में और राजस्थान में होना राजस्थान के पर्यटन और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। अबू आजमी द्वारा औरंगजेब को लेकर दिए बयान पर कहा कि बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है।

कृषि एवं उद्यानिकी सचिव ने फसल कटाई प्रयोगों और फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का धरातल पर लिया जायजा

जयपुर। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने गुरुवार को दौसा व जयपुर जिले का दौरा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत रबी 2024-25 के लिए फसल कटाई प्रयोगों व स्मार्ट सेम्पलिंग तकनीक के माध्यम से खेतों के चयन और फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का धरातल पर जायजा लिया एवं क्रियान्विति की गति बढ़ाने के निर्देश दिये।

शासन सचिव ने दौसा जिले के भाण्ड़ारेंज के भीखली गांव में गेहूं के खेत में फसल कटाई प्रयोगों के चयन की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इसके साथ ही ढ़ाणी बाग में सरसों के खेत में फसल कटाई प्रयोग के तहत फसल कटाई की प्रक्रिया का धरातल पर जायजा लिया व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने भ्रमण के दौरान ई-गिरदावरी किये जाने का भी जायजा लिया।

राजन विशाल ने काली पहाड़ी गांव में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर का अवलोकन किया व वहां मौजूद कृषकों के साथ संवाद भी किया। दौरे के दौरान उन्होंने जयपुर के बस्सी, मानसर खेड़ी में चने के खेत में स्मार्ट सेम्पलिंग तकनीक से ऐप के माध्यम से खेत के चयन की प्रक्रिया का अवलोकन किया।

शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों से कार्यालय में ई-फाईलिंग, फसल बीमा प्रगति की जानकारी, फसल कटाई प्रयोगों, फार्मर रजिस्ट्री शिविरों, उर्वरक नमूना प्रक्रिया व ऑन-लाईन बिल प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषि विभाग की योजनाओं द्वारा ज्यादा से ज्यादा कृषकों को लाभान्वित करे तथा कृषि पर्यवेक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों का आयोजन कर विभागीय योजनाओं की जानकारी कृषकों तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करें।

रिक्त चिकित्सकीय पदों को शीघ्र भरेंगे : गजेन्द्र सिंह

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेशवासियों को सभी आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारी सरकार ने मेड़ता क्षेत्रवासियों की मंशानुसार चिकित्सालय को राजकीय उप जिला अस्पताल मेड़ता में क्रमोन्नत किया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र ही भर दिया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उप जिला अस्पताल मेड़ता में विभिन्न कारणों से परिसर का विस्तार नहीं हो पाया है। वर्तमान में यहां हर माह 21 हजार 750 ओपीडी दर्ज की जा रही है। साथ ही, यहां ट्रोमा सेंटर भी संचालित है।

इससे पहले विधायक लक्ष्मण राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राजकीय उप जिला अस्पताल मेड़ता में स्वीकृत 28 चिकित्सकों के पदों पर 13 चिकित्सक और अराजपत्रित संवर्ग के 72 स्वीकृत पदों में से 41 कार्यरत हैं।

विहिप ने 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की

जयपुर। राजस्थान में कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा पांच हिंदू नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण की घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने बुधवार को 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। विहिप के क्षेत्रीय सचिव सुरेश उपाध्याय ने यहां एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' दोनों ही देशव्यापी समस्या बन गए हैं और राजस्थान भी इनसे अछूता नहीं है।

ब्यावर ब्लैकमेल मामले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों से विभिन्न तरीकों से दोस्ती करते हैं और उनका शोषण करते हैं। हाल ही में ब्यावर जिले में 10 युवकों, जिनमें से आठ मुस्लिम हैं, और तीन नाबालिग लड़कों द्वारा कथित तौर पर पांच नाबालिग लड़कियों का शोषण और ब्लैकमेल किया गया। बिजयनगर पुलिस थाने में मामले दर्ज किए गए। उपाध्याय ने आरोप लगाया, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को धोखा देते हैं, उन्हें फंसाते हैं और फिर उन्हें नशा देकर या धमकाकर उनके अश्लील वीडियो बना उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। मुस्लिम लड़कियां भी इसमें मुस्लिम लड़कों की मदद करती हैं।

किसी को लगता है कि होली के रंग से धर्म भ्रष्ट होता है तो वह उस दिन घर से न निकले : संभल के सीओ

संभल (उप्र)/भाषा। आगामी होली के त्यौहार और रमजान माह में शांति सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को संभल कोतवाली पुलिस थाना में हुई शांति समिति की बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी ने कहा कि यदि किसी को लगता है कि होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वह उस दिन घर से ना निकले। शांति समिति की बैठक में सीओ ने दोनों समुदायों के लोगों से एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का आग्रह किया।

शांति समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीओ चौधरी ने कहा, '' जिस प्रकार से मुस्लिम बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं।'' होली का त्यौहार 14 मार्च को है और इसी दिन जुमा की नमाज भी होगी।

सीओ ने कहा, ''होली का दिन वर्ष में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। यदि किसी को लगता है होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वह उस दिन घर से ना निकले।'' चौधरी ने लोगों से अपील की कि वे उन लोगों को जबरदस्ती रंग ना लगाएं जो होली नहीं मनाना चाहते। सीओ ने कहा कि शांति समिति की बैठक सभी स्तर पर चल रही है। चूंकि संभल में तीन महीने पहले शांति भंग हुई थी इसलिए यहां बेहद सतर्कता बरती जा रही है। चौधरी ने शरारती तत्वों को चेतावनी भी दी और कहा कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उप्र में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करेगी सरकार : योगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गोरखपुर/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के विकास में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में 10 लाख युवा उद्यमी तैयार करने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, भारत नई दिशा में बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन किया जा रहा है। नया भारत ऊर्जा व सामर्थ्य से दुनिया को अपना अनुगामी बनाता है। इस ऊर्जा के प्रतीक हैं युवा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका नए युवा उद्यमियों की होगी।

मुख्यमंत्री ने बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) के तहत गोरखपुर व बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण तथा ओडीओपी के अंतर्गत दोनों मंडलों के 2100 प्रशिक्षणार्थियों को टूलकिट वितरित की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के जरिये सरकार ने व्यवस्था कि है कि एक वर्ष में एक लाख नए उद्यमी, पांच लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएंगे।

योगी ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति, महिला व अति पिछड़ी जाति के लिए अतिरिक्त सुविधा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश ने समृद्धि व खुशहाली के नए दौर में प्रवेश किया है। निर्यात बढ़ा है। हमने उत्तर प्रदेश के अगले स्थापना दिवस पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की, जिससे कारीगर, हस्तशिल्पी सम्मान पा सकें। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि सीएम युवा योजना को इसी शुरुआत के एक महीने के भीतर ही 2.54 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जो पूरे वर्ष के लिए एक लाख उद्यमियों के लक्ष्य से कहीं अधिक है। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि अब तक एक लाख आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिनमें 24,000 लाभार्थियों के लिए 931 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 10,500 आवेदकों को 410 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।

नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाएंगे भारत के ऊर्जावान युवा: बिरला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत के ऊर्जावान और दूरदर्शी युवा पूरी दुनिया में नवाचार और अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 'बिजनेस कॉन्क्लेव' में छात्रों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भारत की प्रगति और विकास में महिलाएं सबसे आगे हैं।

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में वे देश में पथप्रदर्शक के रूप में उभरेंगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के युवा और महिलाएं अपनी बुद्धिमता और कड़ी मेहनत से पूरी दुनिया में परिवर्तनकारी बदलाव लाएंगे। बिरला ने कहा, ''भारत के ऊर्जावान और दूरदर्शी युवा पूरी दुनिया में नवाचार और अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।'' उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे शीघ्र अपनी दिशा तय करें, लक्ष्य निर्धारित करें और दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें प्राप्त करें।

बिरला ने स्वीकार किया कि तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी के परिदृश्य में मानसिक आयामों के विस्तार की अपार संभावना है।

बाबूलाल मरांडी को झारखंड में भाजपा विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रांची/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को धनवार क्षेत्र से विधायक बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा में पार्टी विधायक दल का नेता नियुक्त किया। यहां एक बैठक के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मरांडी को सर्वसम्मति से पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया।

भाजपा ने झारखंड में विधायक दल के नेता के चयन के लिए बुधवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष के. लक्ष्मण को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। यादव ने कहा कि नवीन जायसवाल, नीरा यादव, राज सिन्हा और प्रकाश राम जैसे वरिष्ठ विधायकों ने बैठक के दौरान विधायक दल के नेता के रूप में मरांडी के नाम का प्रस्ताव रखा और इसे सभी ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा, ''राज्य विधानसभा में मरांडी के नेतृत्व में विधायक झारखंड और यहां की जनता की भलाई के लिए काम करेंगे।'' झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी ने उन्हें दी गई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा का आभार जताया। मरांडी ने कहा, ''मैं संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे समर्पण के साथ काम करूंगा और विधानसभा के अंदर और बाहर सभी को एक साथ लेकर चलने का हर संभव प्रयास करूंगा।'' उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता के नाम की सिफारिश पार्टी द्वारा किए जाने के बावजूद जानबूझकर देरी की थी।

गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की जरूरतों की अनदेखी कर रही उप्र सरकार: मायावती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए गरीबों, पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों की जरूरतों की अनदेखी कर उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

मायावती ने यहां लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, सरकार की आर्थिक नीतियों और बजटीय दावों से बड़े पैमाने पर मुट्ठी भर धनी पूंजीपतियों को फायदा होता है। अमीरों को और अमीर बनाने के बजाय सरकार को इस देश के लगभग 125 करोड़ आम नागरिकों के बीच गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही है जबकि राज्य को देश का 'विकास इंजन' कहा जाता है। मायावती ने कहा, इन आवश्यक सेवाओं की खराब स्थिति कोई रहस्य नहीं है। केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी धन की कोई कमी नहीं है लेकिन वंचितों के कल्याण के लिए इसका उपयोग करने में उसकी विफलता बेहद चिंताजनक है। बसपा सुप्रिमो ने भाजपा पर कांग्रेस के समान शासन मॉडल अपनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि अन्य राज्यों में शासन करने वाली क्षेत्रीय पार्टियां भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपना रही हैं।

सुभद्रा योजना के तहत एक करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल: ओडिशा की उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा सरकार ने बृहस्पतिवार को सुभद्रा योजना के तहत 2.30 लाख नई महिला लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपए वितरित किए। महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रभारी उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 2.30 लाख महिलाओं को पांच-पांच हजार रुपए हस्तांतरित किए।

परीदा ने कहा कि पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत किए जाने के बाद से राज्य सरकार ने पांच चरणों में इस योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित की है, जिससे एक करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। सुभद्रा योजना का उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को पांच वर्षों (2024-25 से 2028-29) में 50,000 रुपए प्रदान करना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2024 के अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य की एक करोड़ गरीब महिलाओं को 50,000 रुपए देने का वादा किया था। परिदा ने कहा, अब वह वादा पूरा हो गया है। परिदा ने सुभद्रा योजना के सभी लाभार्थियों से अपील की कि वे अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए सात मार्च की शाम को एक दीया जलाएं।

यादवपुर विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी

राज्यपाल ने कुलपतियों की बैठक बुलाई

कोलकाता/भाषा। यादवपुर विश्वविद्यालय में विरोध-प्रदर्शन बृहस्पतिवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रहा और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एआईडीएसओ) और वामपंथी संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने परिसर के अंदर रैलियां कीं तथा प्रशासनिक भवन के सामने धरना दिया।

इस बीच, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने यादवपुर विश्वविद्यालय गतिरोध पर चर्चा के लिए शुक्रवार को राजभवन में कुलपतियों की एक आपात बैठक बुलाई है। उन्होंने बताया कि यादवपुर विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति से परिसर में छात्रों की हिंसक गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट मिलने के बाद बोस ने यह फैसला लिया। अधिकारी ने बताया, ''राज्यपाल ने यादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से तत्काल रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद कुलाधिपति ने कल (शुक्रवार) सभी कुलपतियों की एक आपात बैठक बुलाई है।''

बीएसएफ ने पेट्रापोल में एक व्यक्ति से 49 लाख रुपए मूल्य का सोना बरामद किया

कोलकाता/भाषा। भारत-बांग्लादेश सीमा के पास पेट्रापोल में बीएसएफ के जवानों ने एक व्यक्ति से 49 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सोना बरामद किया। अर्धसैनिक बल ने बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा कि 'साउथ बंगाल फ्रंटियर' की 145वीं बटालियन के जवानों ने खुद को दुबई का फैशन डिजाइनर बताने वाले व्यक्ति को पकड़ा। इसमें कहा गया कि उसने चूरे के रूप से 564 ग्राम सोना पॉलीथिन में लपेटकर अपनी गुदा में छिपाया हुआ था। जब्त किए सोने के चूरे की बाजार में अनुमानित कीमत 49,13,624 रुपए है। बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे व्यक्ति ने खुद को मुंबई का निवासी बताया। बयान में कहा गया, जल्दी पैसे कमाने के लालच में उसने दुबई से बांग्लादेश के रास्ते भारत में सोने की तस्करी की साजिश रची।

अरुणाचल सरकार अवैध जुआ और 'लॉटरी' से सख्ती से निपटेगी: उपमुख्यमंत्री चौना मीन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ईटानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश सरकार अवैध जुआ और अनधिकृत लॉटरी की समस्या से निपटने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करेगी। राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी गई।

अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र विधायक कुमार वाई द्वारा पेश किए गए सदस्य का निजी संकल्प (पीएमआर) का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने स्वीकार किया कि मौजूदा कानूनों के बावजूद, राज्य में अवैध जुआ, अनधिकृत लॉटरी टिकट बिक्री और जबरन दान की समस्याएं जारी हैं। मीन ने विधानसभा को आश्वासन दिया कि सरकार इस समस्या पर अंकुश लगाने के मकसद से कानूनों को सख्ती के साथ लागू करेगी। निजी संकल्प पेश करते हुए वाई ने सरकार से अनधिकृत लॉटरी और 'हाउसी' गेम टिकट की बड़े पैमाने पर बिक्री, साथ ही अवैध दान संग्रह को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विशेष रूप से राज्य की राजधानी ईटानगर में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मीन ने कहा कि सरकार ने पहले ही उपायुक्तों को मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्देश दे दिया है। मीन ने कहा, ''अवैध जुए ने राज्य में कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है, लोग लाभ की उम्मीद में अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। कानून पहले से ही लागू हैं, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ऐसी गतिविधियों में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया है।'' उन्होंने वाई से संकल्प वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा, ''हमें लोगों को शिक्षित करना होगा और ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए नागरिक कर्तव्य की भावना पैदा करनी होगी।''

चर्चा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता पानी ताराम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य में कई संगठन नेक कार्यों के लिए दान एकत्र करने का दावा करते हैं और इसके लिए अक्सर निश्चित राशि निर्धारित कर दी जाती हैं, जिससे यह स्वैच्छिक योगदान के बजाय

गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रोजा ना रखकर गुनाह किया: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बरेली/भाषा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रमजान में रोजा नहीं रखकर गुनाह किया है। उन्होंने कहा कि शरीयत की नजर में शमी मुजरिम हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।

मौलाना शहाबुद्दीन ने एक वीडियो में कहा कि शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान मैदान में एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए। रजवी ने शमी को सलाह दी कि वह शरीयत के नियमों का पालन करें। शरीयत के नियमों का पालन करना सभी मुसलमानों की जिम्मेदारी है और इस्लाम में रोजा रखना फर्ज है। रजवी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर रोजा नहीं रखता तो वह इस्लामिक कानून के अनुसार गुनाहगार माना जाता है। क्रिकेट खेलना बुरा नहीं है लेकिन धार्मिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। मैं हिदायत देता हूं कि शमी शरीयत के नियमों का पालन करें और अपने धर्म के प्रति जिम्मेदार बनें।

संसद सत्र में उठाया जाएगा वोटर आईडी संख्या के दोहराव का मुद्दा: ओब्रायन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान मतदाता पहचान पत्र संख्या के दोहराव का मुद्दा दोनों सदनों में उठाएगी।

पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार संसद में असहमति को दबाने का प्रयास कर रही है।

राज्यसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता ने एक ब्लॉग में कहा कि कई विपक्षी दलों ने कहा है कि वे पहले गृह मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं।

ओब्रायन ने कहा, ''संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग कुछ ही दिनों में (10 मार्च) शुरू हो रहा है...वोटर आईडी संख्या के दोहराव का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। यह मामला पिछले हफ्ते तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में उठाया था।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कोई मामूली त्रुटि नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर असर डालने वाला एक गंभीर मामला है।

मेरा काम खेल को बढ़ावा देना, अदालत में चल रहे मामले से चिंतित नहीं: ब्रिजिंदर सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अभी तक अदालत से यही संकेत मिला है कि हम सही हैं। इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। अगर कल अदालत मुझसे कहती है कि हमारा गुट सही नहीं है तो मैं अपने पद से हट जाउंगा।

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय गोल्फ संघ (आईजीयू) के अध्यक्ष ब्रिजिंदर सिंह ने खेल मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय संस्था के समर्थन का हवाला देते कहा कि वह हरीश शेट्टी की अगुवाई वाले प्रतिद्वंद्वी गुट द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे से चिंतित नहीं हैं।

सिंह ने कहा कि उनकी अगुवाई वाले गुट को खेल मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय संस्था का समर्थन प्राप्त है और उनका काम खेल को बढ़ावा देना है।

सिंह और पूर्व महासचिव शेट्टी के बीच अंदरूनी कलह और मतभेद के कारण दिसंबर में आईजीयू के दो अलग-अलग चुनाव हुए।

खेल मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय गोल्फ महासंघ (आईजीएफ) ने सिंह गुट को मान्यता दी, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने शेट्टी गुट का समर्थन किया।

खेल मंत्रालय और आईजीएफ ने इन चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए आईओए को फटकार लगाई थी। इस फैसले से नाखुश शेट्टी गुट ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले की पहली सुनवाई तीन मार्च को हुई और अगली सुनवाई 27 मार्च को तय की गई। सिंह ने यहां हीरो इंडिया ओपन 2025 के लिए आयोजित कार्यक्रम में 'भाषा' से कहा, '' आप अगर यह सोचना शुरू कर दें कि क्या हो रहा है और इस पर काम करना शुरू कर दें तो इससे कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि आखिरकार अदालत ही आदेश देगा।'' उन्होंने कहा, '' अभी तक अदालत से यही संकेत मिला है कि हम सही हैं। इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। अगर कल अदालत मुझसे कहती है कि हमारा गुट सही नहीं है तो मैं अपने पद से हट जाउंगा।'' उन्होंने कहा, '' मेरी जिम्मेदारी मौजूदा परिषद के अध्यक्ष के रूप में ईमानदारी से काम करना और खेल को बढ़ावा देना है। मैं यही कर रहा हूं। मैं एक अध्यक्ष के रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा हूं क्योंकि मुझे मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय गोल्फ महासंघ और यहां तक कि अदालत से अभी तक यही संकेत मिला है। इसलिए मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं।''

सिंह ने कहा कि गोल्फ प्रबंधन कंपनी केएंडए गोल्फ के सहयोग से आईजीयू 24 मार्च को गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल 'सुपर 6' की मेजबानी करेगा। उन्होंने ने बताया, ''यह जमीनी स्तर पर गोल्फ को बढ़ावा देने की एक नई शुरुआत है।

खेल मंत्रालय ने कहा, खिलाड़ियों के लिए एक समान चयन नीति और शिकायत निवारण प्रणाली हो

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। जवाबदेही और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के लिए अपनी चयन नीतियों का मानकीकरण करना, खिलाड़ियों को ट्रायल्स के बारे में कम से कम 15 दिन पहले सूचित करना और अन्याय की भावना के कारण होने वाले मुकदमों में कमी लाने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है।

चयन मामलों पर निर्देश तब आए हैं जब खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय महासंघों को स्पष्ट कर दिया था कि वह चाहते हैं कि एनएसएफ खिलाड़ियों के साथ कानूनी टकराव से बचें जैसा कि हाल के दिनों में कुश्ती, निशानेबाजी और कुछ शीतकालीन खेलों की प्रतियोगिताओं में देखा गया है। पीटीआई के पास मौजूद यह सर्कुलर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) और राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को भेजा गया है। नए निर्देशों के अनुसार एनएसएफ को अपनी वेबसाइट पर चयन नीतियों की जानकारी देना अनिवार्य है और इसमें संशोधन तभी संभव है जबकि प्रतियोगिता के आयोजन में कम से कम तीन महीने का समय हो। चयन ट्रायल की वीडियोग्राफी करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

पांच पन्नों के दस्तावेज में एनएसएफ के लिए हर ट्रायल से पहले मंत्रालय को सूचित करना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अनुसार, ''वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के दौरान चयन ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग को चयन समिति की बैठक की हस्ताक्षर सहित जानकारी के साथ साइ को भेजा जाएगा।''

मंत्रालय ने एनएसएफ से कहा है कि वे ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल, पैरा एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं के लिए चयन मानदंड कम से कम दो साल पहले सार्वजनिक करें।

निशानेबाजी जैसे खेल में लंबे समय से यह मांग की जा रही थी। प्रसिद्ध पिस्टल कोच जसपाल राणा कह चुके हैं कि मानकीकृत नीतियां नहीं होने का खिलाड़ियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन बड़ी प्रतियोगिताओं की सूची में खिलाड़ियों, कोच, सहायक कर्मचारियों और अधिकारियों को मंत्रालय को सूचित किए बिना शामिल नहीं किया जा सकता और 'प्रस्तावित नामों के लिए तर्क और आधार' भी देने होंगे। यह सूची प्रविष्टियां सौंपने की अंतिम तिथि से कम से कम 30 दिन पहले मंत्रालय/साइ को भेजी जानी चाहिए।

ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए जहां खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा होना जरूरी है वहां मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि एनएसएफ उन्हें ट्रेनिंग शुरू होने से कम से कम तीन महीने पहले जरूरी आवश्यकताओं के बारे में सूचित करें। यदि कोई खिलाड़ी इसके बावजूद व्यवस्था से परेशान है तो एनएसएफ को शिकायत निवारण समिति या अपील समिति बनाने का निर्देश दिया गया है जो शिकायत के सात दिनों के भीतर निर्णय लेगी। सर्कुलर के अनुसार, ''इस (समिति) में अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्होंने कम से कम चार साल पहले सक्रिय खेलों से संन्यास लिया हो।'' इसमें कहा गया, ''चयन समिति का कोई भी सदस्य शिकायत निवारण समिति का हिस्सा नहीं होगा। ऐसी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए संक्षिप्त प्रकृति की होगी।

सुविचार

इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला.. ताला जब खुलता है तब मालूम होता है कि, दुकान सोने की है या कोयले की।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सतर्कता से साजिश नाकाम

गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) और हरियाणा पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) की संयुक्त टीम ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर पर हमले की साजिश को नाकाम कर सराहनीय कार्य किया है। हमारी एजेंसियां अपनी सतर्कता से ऐसी घातक साजिशों को कई बार नाकाम कर चुकी हैं। उनके बारे में आम जनता को पता ही नहीं होता। गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने जिस युवक को गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा एक खाली मकान में दो हथगोले छिपाए जाने की बात सामने आई है। अगर यह शख्स किसी तरह एजेंसियों की पैनी नजर से बच जाता और अयोध्या पहुंचकर कोई बड़ी वारदात कर देता तो भारी नुकसान हो सकता था। उक्त आरोपी की पहचान करने, उस तक पहुंचने और गिरफ्तार करने तक एटीएस और एसटीएफ के जिन अधिकारियों ने अपना कर्तव्य निभाया है, वे प्रशंसा के पात्र हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी यहां खत्म नहीं हो जाती, बल्कि बढ़ जाती है। अब आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाकर केस को मजबूत बनाएं, ताकि अदालत में उसका कच्चा चिट्ठा खुल जाए और वह उचित दंड पाए। यह मामला इस किस्म की विषैली मानसिकता रखने वालों के लिए एक चेतावनी होना चाहिए कि किसी के उकसावे में आकर ऐसा निंदनीय कृत्य करने का मंसूबा बना रहे हैं तो यह न समझें कि आप पर किसी की नजर नहीं है या बच जाएंगे। देश की एजेंसियां हमेशा सतर्क और सजग हैं। जो इस देश को नुकसान पहुंचाने, सद्भाव को नष्ट करने के लिए 'दुष्ट ताकतों' का मोहरा बनेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

श्रीराम मंदिर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बनाया गया है। उस मामले से जुड़े जितने भी संशय थे, वे दूर किए जा चुके हैं। अब सबको इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सभी सबूत साफ-साफ कह चुके हैं कि यही श्रीराम जन्मभूमि है, पहले यहां मंदिर ही था। भारत के न्यायालयों में वर्षों इस मुकदमे पर सुनवाई हुई, कई-कई घंटों बहस हुई, एक-एक सबूत को बार-बार जांचा-परखा गया, हर आपत्ति का तर्क सहित निवारण किया गया, लिहाजा सच खुलकर सामने आ गया है। इसका सम्मान करना चाहिए। विदेशी आक्रांताओं ने अपने घृणित कार्यों से भारतीय समाज के सद्भाव को चोट पहुंचाने के लिए अनेक मंदिरों का अपमान किया था। वे यहां कोई जनकल्याण करने नहीं आए थे। वे लूटमार करने के इरादे से आए थे। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि हकीकत है। कुछ कथित बुद्धिजीवियों ने उनका 'महिमामंडन' करते हुए यह झूठा प्रचार कर रखा है कि उन्होंने यहां आकर संस्कृति को समृद्ध किया, सुंदर इमारतें बनवाईं! जरा यह तो मालूम करें कि वे (आक्रांता) जिन देशों से आए थे, वहां स्थापत्य कला के क्षेत्र में कौनसा कीर्तिमान रच दिया था? उनके 'शासन काल' में यहां बनाई गईं इमारतों में हमारे ही पूर्वजों का खून-पसीना लगा था, इसलिए आक्रांताओं की वाहवाही तथ्यहीन एवं निराधार है। हां, पाकिस्तानी मीडिया उनकी शान में कसीदे खूब पढ़ता रहता है। वह उनकी फर्जी महानता की कहानियां सुनाकर उन्हें संयमी, न्यायप्रिय और मानवता का प्रेमी बताता रहता है। कुछ पाकिस्तानी 'उपदेशक' भी सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। वे स्थानीय मीडिया के सुर में सुर मिलाते हुए श्रीराम मंदिर के संबंध में दुष्प्रचार कर रहे हैं। वे पाकिस्तानी युवाओं को तो भ्रमित कर चुके हैं। वहीं, भारतीय युवाओं को भी भड़का रहे हैं। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई उन युवाओं को इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। वे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कहीं बैठकर युवाओं को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। जो उनके उकसावे में आकर यहां गलत मंसूबे बनाएगा, उसकी 'खातिरदारी' एटीएस और अन्य एजेंसियां अपने तरीके से करना जानती हैं।

ट्वीटर टॉक

आबू रोड में दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को घायल का समुचित उपचार कराने हेतु उचित निर्देश दिए गए हैं।

-भजनलाल शर्मा

कार्तिकेय और अमानत ने जन्मदिन पर श्री रामचरितमानस भेंटकर भावुक कर दिया। श्री रामचरितमानस हमारे देश के जीवनमूल्य और संस्कृति के अनुरूप है। जो कहते है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई; मैंने जीवन में इसे ही उतारने का प्रयत्न किया है।

-शिवराजसिंह चौहान

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के साथ लक्ष्यद्वीप और पुदुचेरी की भी सांस्कृतिक विरासत का साक्षात्कार किया जा सकता है।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत

प्रेरक प्रसंग

चाणक्य की दूरदृष्टि

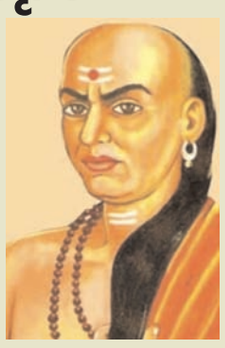

एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से जिज्ञासावश पूछा, 'आपकी खोजपूर्ण दृष्टि को मेरा डील-डौल युक्त शरीर इतना विशेष क्योंकर लगा था?' चाणक्य ने रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ सरलता से बताया, 'किशोर चंद्रगुप्त मुझे शासक की भूमिका में खेलते हुए मिले थे। जंगल में वह राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। कम आयु में भी चंद्रगुप्त में शासक जैसा संतुलन और समझदारी थी। ऐसी समझ और आत्मविश्वास केवल वही व्यक्ति दिखा सकता है, जो अपने परिवेश को गहरे से समझता हो। तुम बंधकर रहने वाले नहीं, सम्राट बनकर विस्तार पाने वाले हो, चंद्रगुप्त। यह तुमने सिद्ध भी कर दिया है।' चाणक्य की बात सौ प्रतिशत सही थी।

सामयिक

सार्थक भागीदारी के बिना कैसे हल होंगे आधी दुनिया के मसले?

प्रियंका सौरभ

मो.: 7015375570

स्कूली पाठ्यक्रम में कम उम्र से ही पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने के लिए लिंग जागरूकता को शामिल किया जाना चाहिए। समानता-केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यपुस्तकों में लिंग-संवेदनशील सामग्री शामिल होनी चाहिए। कंपनियों के लिए गहन ऑडिट आयोजित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मातृत्व और उत्पीड़न विरोधी नियमों का अनुपालन करती हैं। कोई भी देश अपनी आधी आबादी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। लिंग-संवेदनशील नीतियों को विकसित करने के लिए निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी महत्त्वपूर्ण है।

हमारे देश में महिलाएँ जनसंख्या का लगभग 48% हिस्सा हैं, फिर भी वे लोकसभा सीटों के 15% से भी कम पर कब्जा करती हैं। इस महत्त्वपूर्ण अल्प प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप कार्यस्थल सुरक्षा, अवैतनिक देखभाल ज़िम्मेदारियाँ और आर्थिक अधिकार जैसे महिला मुद्दों की अनदेखी होती है। इस तरह का बहिष्कार पितृसत्तात्मक मानदंडों को बनाए रखता है। फिर भी, ऐसे भेदभाव को दूर करने, कानूनी सुरक्षा बढ़ाने और संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करने में न्यायिक कार्यवाही महत्त्वपूर्ण रही है, हालाँकि गहरी जड़ें जमाए हुए पूर्वाग्रहों को मिटाने में उनकी सफलता अभी भी चर्चा का विषय है। महिला प्रतिनिधित्व की कमी से मातृ अधिकारों का हनन होता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर भेदभाव होता है और पर्याप्त सहायता की कमी होती है। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 सवेतन अवकाश प्रदान करता है, लेकिन निजी क्षेत्र में इसका कार्यान्वयन कम है, जो महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने से हतोत्साहित करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया से महिलाओं को बाहर रखने से महिला सशक्तिकरण की कड़ी कमजोर होती है। इसके पीछे की वजहें हैं लैंगिक पूर्वाग्रह और भेदभाव, कार्यस्थल संस्कृति, सामाजिक और पारिवारिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी न होने से महिलाओं को दरकिनार किया जाता है। इससे दायरा सीमित हो जाता है और इस सीमित दायरे में आने वाली चुनौतियों का सामना करना मुश्किल होता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के मुताबिक, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी ना केवल उनका अधिकार है, बल्कि यह सार्वजनिक निर्णयों में उनके हितों का सम्मान करने की अनिवार्य शर्त भी है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा था कि लोकतंत्र का स्तर मूल रूप से महिलाओं के सशक्तीकरण पर निर्भर करता है। इस असमानता को कम करने के लिए शिक्षा के ज़रिए महिलाओं को सशक्त बनाना, उत्पीड़न से मुक्त और सुरक्षित वातावरण बनाना, लड़कियों को जीवन कौशल सिखाना, हिंसा को ख़त्म करना पहली आवश्यकता है।

वर्तमान नीतियाँ लचीली कार्य व्यवस्था प्रदान नहीं करती हैं, परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए अपने पेशेवर और घरेलू जीवन को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई कार्यस्थल पॉश अधिनियम 2013 का अनुपालन नहीं करते हैं, क्योंकि पुरुष-प्रधान नेतृत्व अक्सर महिलाओं की सुरक्षा की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को अनदेखा करता है। इसके अतिरिक्त, नीतियाँ महिला उद्यमियों को समान ऋण और व्यावसायिक प्रोत्साहन प्राप्त करने में पर्याप्त रूप से सहायता नहीं करती हैं, जो उनके आर्थिक सशक्तीकरण को सीमित करती हैं। हालांकि न्यायालयों ने मातृ सुरक्षा को मज़बूत करके लिंग-संवेदनशील कार्यस्थलों को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है। 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने दो महिला न्यायाधीशों को बहाल किया, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि गर्भावस्था से सम्बंधित बर्खास्तगी दंडनीय और अवैध दोनों है, जिससे कार्यस्थल समानता को बढ़ावा मिलता है। न्यायिक निर्णयों ने महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भेदभावपूर्ण धार्मिक प्रथाओं को भी उलट दिया है। उदाहरण के लिए, 2017 में शायरा बानो मामले ने ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित कर दिया, जिससे मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकार सुरक्षित हो गए। इसके अलावा, अदालतों ने हिंदू उत्तराधिकार कानूनों में पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हुए समान उत्तराधिकार अधिकारों को बरकरार रखा है, जैसा कि 2020 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देखा गया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करें। प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए चुनावों में महिला आरक्षण विधेयक को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। न्यायालयों को लिंग कानूनों के पालन की निगरानी और प्रवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे प्रभावी नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। फास्ट-ट्रैक न्यायालयों को कार्यस्थल उत्पीड़न की घटनाओं के लिए त्वरित न्याय प्रदान करना चाहिए। नीतियों को महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और उद्यमिता समर्थन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए बड़े ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए।

स्कूली पाठ्यक्रम में कम उम्र से ही पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने के लिए लिंग जागरूकता को शामिल किया जाना चाहिए। समानता-केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यपुस्तकों में लिंग-संवेदनशील सामग्री शामिल होनी चाहिए। कंपनियों के लिए गहन ऑडिट आयोजित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मातृत्व और उत्पीड़न विरोधी नियमों का अनुपालन करती हैं। कोई भी देश अपनी आधी आबादी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। लिंग-संवेदनशील नीतियों को विकसित करने के लिए निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। उन्हें विधायी सुधारों, जमीनी स्तर पर शिक्षा और संस्थागत प्रवर्तन तंत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक भागीदारी और कानूनी सुरक्षा को बढ़ाने से भारत के लिए वास्तव में न्यायसंगत और समावेशी शासन प्रणाली बनेगी। महिलाओं की आवाज़, दृष्टिकोण और प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने के लिए, महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों सहित महिलाओं की सार्थक भागीदारी और नेतृत्व को मानवीय कार्यवाही के सभी स्तरों पर बढ़ावा दिया जाना ज़रूरी है।

केवल महिला दिवस पर ही नहीं, हर रोज़ महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस बदलाव के लिए, अपने हक़ों के लिए। छोटी शुरुआत ही सही, लेकिन शुरुआत सबको करनी पड़ेगी। ये संघर्ष का सफ़र अंतहीन है। महिलाओं के लिए समान वेतन हो, उन्हें फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। मैं एक ऐसा समाज चाहती हूँ, जहाँ बराबरी के लिए महिलाओं को बार-बार अपनी छाती पीटकर अपनी पहचान न साबित करनी पड़े, अवसर सबको मिले। महिलाओं को अपने टैलेंट के दम पर काम मिले, उसे सराहा जाए, उसकी कद्र हो। घर और काम की जगह पर महिला होने के नाते सहानुभूति नहीं चाहिए, सिर्फ़ बराबरी चाहिए। जो स्वाभाविक हो, उसके लिए संघर्ष न करना पड़ा।

नजरिया

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उच्छृंखलता नामंजूर

ललित गर्ग

मो. 9811051133

सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई के दौरान जो कहा, वह जहां संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से खासा अहम है वही एक संतुलित एवं आदर्श समाज व्यवस्था का आधार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े इन मामलों में जो फैसले किए हैं और इस दौरान जो टिप्पणियां की हैं, उसके निहितार्थों को समझने की आवश्यकता है। मंगलवार को 'मियां-टियां' और 'पाकिस्तानी' शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मुकदमे के आरोपी को इस आधार पर आरोप-मुक्त कर दिया कि यह भारतीय दंड सहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध के बराबर नहीं है। वैसे, अदालत ने इन शब्दों के प्रयोग को गैर-मुनासिब माना। एक दूसरे रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले में अश्लीलता के आरोपों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संतुलित लेकिन धारदार-सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि न तो अश्लीलता के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिए और न ही इसे अभिव्यक्ति की आजादी की राह में आने देना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया को पॉडकास्ट जारी रखने की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह नैतिकता और अश्लीलता की सीमा को लांघने की गलती न करें। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी इन जटिल होती स्थितियों को गंभीरता से लिया और अनेक धुंधलकों को साफ किया है। सर्वोच्च न्यायालय के इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जुड़े फैसलों रूपी उजालों का स्वागत होना ही चाहिए।

यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी न्याय प्रक्रिया की विसंगति ही है कि एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस्तेमाल इन 'मियां-टियां' और 'पाकिस्तानी' जैसे शब्दों से जुड़े मुकदमे को निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक का सफर तय करने में लगभग चार साल लगे, मगर दोनों पक्षों ने किसी पड़ाव पर यह समझदारी दिखाने की कोशिश नहीं की कि यह सिर्फ अहं की लड़ाई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक कविता पर गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस मामले में जांच की जरूरत बताते हुए पुलिस कार्रवाई की पुष्टि की थी। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी मायने रखती है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस को कविता पढ़नी चाहिए थी। कविता नफरत और हिंसा की नहीं, इंसाफ और इश्क की बात करती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। कम से कम अब तो पुलिस को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मर्म समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बात का संदेश बिल्कुल स्पष्ट एवं न्यायसंगत है। हालांकि यह छिपी बात नहीं है कि पुलिस स्वायत्त तरीके से काम नहीं करती। अनेक कार्रवाइयां उसे सत्ता पक्ष के दबाव में करनी पड़ती हैं। इसलिए विपक्षी दलों एवं समुदाय विशेष के मामले में अगर अभिव्यक्ति की आजादी के कानून को हाशिये पर धकेल दिया या नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो हैरानी की बात नहीं। यह कम बड़ी विडंबना नहीं कि साहित्य और कलाओं में अभिव्यक्त विचारों की व्याख्या भी अदालतों को करनी पड़ रही है। सत्ताएं सदा से अपनी आलोचना से तल्ख हो जाती रही है, ऐसी जटिल स्थितियों में आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा?

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई मौकों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लम्बी बहसें हो चुकी हैं, आन्दोलन तक हुए, हिंसा एवं अराजकता का माहौल बना। हर बार अदालतें पुलिस को नसीहत देती हैं, अपने दखल से समझ एवं सीख भी देती है ताकि संतुलित वातावरण बना रहे। मगर शायद उस पर संजीदगी एवं संवेदनशीलता से अमल की जरूरत न तो पुलिस ने समझी और न उग्र एवं विध्वंसक शक्तियों ने। इसी का नतीजा है कि अब भी जब तब ऐसे मामले अदालतों में पहुंच जाते हैं, जिनसे किसी की भावना के आहत होने एवं विभिन्न समुदायों के आपसी सौहार्द-सद्भावना के खण्डित होने के आरोप लगते रहते हैं, जबकि वास्तव में उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। बेवजह नफरत, द्वेष एवं घृणा का माहौल बनता रहा है, चाहे वह फिल्मों के दृश्यों-संवादों, किसी राजनेता के बयानों, धर्मगुरुओं के बोलों या साहित्य के किसी अंश को लेकर भावनाएं आहत करने या भड़काने के आरोप किसी ऐतिहासिक-मिथकीय प्रसंग को लेकर की गई टिप्पणी पर लगते रहे हों।

आज सोशल मीडिया जैसे मंचों के बेजा इस्तेमाल की प्रवृति बढ़ रही है, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब जैसे सोशल मंचों पर ऐसी सामग्री परोसी जा रही है, जो अशिष्ट, अभद्र, हिंसक, भ्रामक, राष्ट्र-विरोधी एवं समुदाय विशेष के लोगों को आहत करने वाली होती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को जोड़ना नहीं, तोड़ना है। इन सोशल मंचों पर ऐसे लोग सक्रिय हैं, जो तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास करते हैं, वे चरित्र-हनन और गाली-गलौच जैसी ओछी हरकतें करने के लिये उद्यत रहते हैं तथा उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक नीति अपनाते हुए अराजक माहौल बनाते हैं। एक प्रगतिशील, सभ्य एवं शालीन समाज में इस तरह की हिंसा, अश्लीलता, नफरत और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडम्बना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चलते सरकार इन अराजक स्थितियों पर काबू नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े मंचों के दुरुपयोग पर चिंता से सहमति जताते हुए भी सेंसरशिप और नॉर्म (मानदंड) के बीच के फर्क को रेखांकित किया। उसका कहना था कि सरकार को इस संबंध में गाइडलाइंस लानी चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी पर गैरजरूरी पाबंदियों का रूप न ले लें।

सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह ऐसे समय सामने आया है जब देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विभिन्न समुदायों का विचलन, द्वेष एवं नफरत काफी बढ़ी हुई दिख रही है। शासन प्रशासन की ओर से इन्हें रोकने की कोशिशों में भी अक्सर अति-उत्साह की झलक देखने को मिलती है। हालांकि सोशल मीडिया के ये मंच स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक भूमिका भी निभाते देखे जाते रहे हैं। उन पर कड़ाई से बहुत सारे ऐसे लोगों के अधिकार भी बाधित होने का खतरा है, जो स्वस्थ तरीके से अपने विचार रखते और कई विचारणीय मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। मगर जिस तरह बड़ी संख्या में वहां उपद्रवी, हिंसक, राष्ट्रीय और सामाजिक समरसता को छिन्न-भिन्न करने वाले तत्त्व सक्रिय हो गए हैं, उससे चिंता होना स्वाभाविक है। इससे जहां नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, वहीं इसके गलत इस्तेमाल की बेजा स्थितियां भी देखने को मिलती है। शीर्ष अदालत ने याद दिलाया है कि इस अधिकार का ख्याल रखा जाए। उन पर अंकुश लगाने एवं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करना जरूरी है।

भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के विरुद्ध वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। सरकार इनकी रक्षा के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के साथ-साथ सेंसरशिप के प्रति अपनी अनिच्छा को दोहराया। लेकिन यह भी कहा कि ऐसा विचार 'घटिया विचारों' और 'गंदी बातों' का लाइसेंस नहीं है। दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया में जिस पैमाने पर विष-वमन हो रहा है, उसने पुलिस की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। मगर उसकी कार्रवाइयां इसलिए प्रभावी नहीं होतीं, क्योंकि राज्य-दर-राज्य उनके पीछे के राजनीतिक पक्षपात भी स्पष्ट हो जाते हैं। राज्य पुलिस अक्सर सरकार विरोधी पोस्ट के मामले में तो तत्परता दिखाती है, मगर सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों की वैसी ही गतिविधियां वह नजरअंदाज कर देती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही गुजरात पुलिस को एहसास कराया है कि उसे असामाजिक तत्वों से निपटते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा भी करनी है। जाहिर है, उच्छृंखल हुए बिना आजादी के उपयोग में ही नागरिक का भी भला है और समाज का भी।

भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के विरुद्ध वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। सरकार इनकी रक्षा के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के साथ-साथ सेंसरशिप के प्रति अपनी अनिच्छा को दोहराया। लेकिन यह भी कहा कि ऐसा विचार 'घटिया विचारों' और 'गंदी बातों' का लाइसेंस नहीं है।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

रेणुका शहाणे अपनी अगली फिल्म की पटकथा पर काम कर रहीं हैं

मुंबई/भाषा। अभिनेत्री-निर्देशक रेणुका शहाणे अपनी अगली फिल्म की पटकथा पर काम कर रही हैं जिसमें उनके पति आशुतोष राणा नजर आ सकते हैं। वह इस फिल्म का निर्देशन भी करेंगी। शहाणे को 'हम आपके हैं कौन', 'मासूम' और 'दिल ने जिसे अपना कहा' जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी अगली फिल्म पुलिस और राजनीति पर आधारित एक हास्य फिल्म होगी।

शहाणे ने पीटीआई-भाषा को बताया, फिल्म निर्देशन मेरा जुनून है और मैं फिल्म की पटकथा लिख रही हूं। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कब दर्शकों के पास पहुंचेगी, क्योंकि मैं अभी पटकथा लिख रही हूं... उम्मीद है कि इसमें मैं आशुतोष राणा के साथ काम करूंगी। शहाणे ने वर्ष 2009 में मराठी फिल्म 'रीटा' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। यह फिल्म उनकी मां शांता गोखले के उपन्यास 'रीटा वेलिंगकर' पर आधारित थी।

हमारे उद्योग में हर तरह की फिल्म बनाने की क्षमता : रीमा कागती

नई दिल्ली/भाषा। 'सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव' की निर्देशक रीमा कागती का मानना है कि भारतीय फिल्म उद्योग में सिर्फ बड़े सितारों वाली मसाला फिल्म ही नहीं, बल्कि हर तरह की फिल्म बनाने की क्षमता है और दर्शक भी ऐसी फिल्मों को अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं।

मालेगांव के फिल्मकार नासिर शेख के जीवन पर आधारित 'सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव' ने पिछले हफ्ते सिनेमाघरों में दस्तक दी।

'हनीमून ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड', 'तलाश' और 'दहाड़' जैसी फिल्मों के लिए दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों की भी वाहवाही लूटने वाली रीमा ने 'पीटीआई-भाषा' के साथ साक्षात्कार में उम्मीद जताई कि लोग तथाकथित कम चर्चित नामों वाली फिल्मों को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाएंगे और ओटीटी पर उनके प्रदर्शन का इंतजार नहीं करेंगे।

रीमा ने कहा, ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर चिंता होती है, जिनसे कोई बड़ा नाम या सितारा नहीं जुड़ा होता है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर लोगों को हमेशा यह सवाल करते हुए देखती हूं कि हम नए अभिनेताओं और लेखकों को मौका क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, और सच कहूं तो, बहुत से लोगों ने अच्छी फिल्म बनाई हैं, जिन्हें सिनेमाघरों में दर्शक नहीं मिलते। और फिर ये ओटीटी मंच पर आती हैं और हर कोई इनकी तारीफों में कसीदे पढ़ने लगता है तथा इन्हें कमतर आंकी गई फिल्मों में शुमार करने लगता है। लेकिन, वास्तव में आपने एक दर्शक के रूप में इन फिल्मों को कमतर आंका, क्योंकि जब आप खुद इन्हें देखने नहीं गए, तो आप दूसरे से सवाल नहीं कर सकते कि उन्होंने इन फिल्मों को क्यों नहीं देखा।

रीमा ने माना कि फिल्म उद्योग ने पिछले साल अच्छा कारोबार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रतिभाएं, सपने और निर्माता हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक खराब साल को अंत के तौर पर देखा जाना चाहिए... मेरा मानना है कि हमारी इंडस्ट्री में हर तरह की फिल्म बनाने की क्षमता है, क्योंकि यही एक फलते-फूलते उद्योग की पहचान है। और हमारे दर्शकों में भी अलग-अलग तरह की फिल्मों को स्वीकार करने की क्षमता है, सिर्फ बड़े सितारों से सजी मसाला फिल्मों को ही नहीं।

दुनिया की सबसे बुजुर्ग हज्जाम 108 साल की जापानी महिला

टोक्यो/एपी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग हज्जाम भले ही 108 साल की है लेकिन दुबली-पतली एवं सफेद बालों वाली इस जापानी महिला की तत्काल अपने काम से सेवानिवृत होने की कोई योजना नहीं है।

शित्सुई हाकोइशी नामक इस बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस सप्ताह 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' द्वारा औपचारिक मान्यता मिलने से उन्हें बहुत खुशी मिली है। बुधवार को उन्हें इस अंतरराष्ट्रीय फ्रैंचाइज़ की ओर से आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में पुरुष हज्जामों के लिए एक अलग श्रेणी है, लेकिन 2018 में 107 वर्ष की आयु में प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले अमेरिका के एंथनी मैनसिनेली की इस बीच मृत्यु हो गई, जिससे हाकोइशी इस रिकॉर्ड की एकमात्र धारक रह गईं।हाकोइशी नौ दशक से इस पेशे में हैं तथा उनका कहना है कि इसका श्रेय उनके ग्राहकों को जाता है।टोक्यो के उत्तर-पूर्व में तोचिगी प्रांत में अपने गृहनगर नाकागावा में एक व्यायामशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में हाकोइशी ने कहा, ''मैं केवल अपने ग्राहकों की वजह से ही इस स्तर पर पहुंच पाई हूँ। मैं अभिभूत हूं और खुशी से भर गई हूं।''यह प्रेस वार्ता बुधवार को टेलीविजन पर प्रसारित हुई।

नाकागावा के एक किसान परिवार में 10 नवंबर, 1916 को जन्मीं हाकोइशी ने 14 साल की उम्र में हज्जाम बनने का फैसला किया और टोक्यो चली गईं, जहां उन्होंने प्रशिक्षु के रूप में अपने हुनर को निखारा। उन्होंने 20 साल की उम्र में हज्जाम के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया और अपने पति के साथ मिलकर एक सैलून खोला। हाकोइशी ने कहा कि वह अपनी कैंची छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

विदाई समारोह

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया डॉ. मल्लिका नड्डा, स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष और अन्य बुधवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इटली के ट्यूरिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के लिए भारतीय दल के विदाई समारोह के दौरान।

कोविड के दौरान 'रणनीतिक नेतृत्व' के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बारबाडोस का प्रतिष्ठित पुरस्कार

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए प्रतिष्ठित 'ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने बारबाडोस के ब्रिजटाउन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक है।

उसने कहा, पुरस्कार की घोषणा बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले ने 20 नवंबर, 2024 को गुयाना के जॉर्जटाउन में दूसरे भारत-कैरिकॉम नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में की थी।

बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए दिया गया है। इसमें कहा गया कि मोटले ने महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समर्थन को मजबूत करने में मोदी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री की ओर से पुरस्कार प्राप्त करते हुए मार्गेरिटा ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रतिनिधित्व करना और उनकी ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकार करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है।

बयान में मार्गेरिटा के हवाले से कहा गया, यह मान्यता भारत और बारबाडोस के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों, तथा विशेष रूप से संकट के समय में सहयोग और विकास के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

बयान में कहा गया है कि 1966 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत और बारबाडोस ने निरंतर जुड़ाव और विकास पहलों के साथ एक मजबूत साझेदारी को बढ़ावा दिया है।

बिहार में फूहड़ भोजपुरी और हिन्दी गानों पर सरकार पूर्ण प्रतिबंध लगाए : नीतू चन्द्रा

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नीतू चन्द्रा श्रीवास्तव ने बिहार सरकार से फूहड़ भोजपुरी और हिन्दी गानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। नीतू चंद्रा श्रीवास्तव ने कहा कि ,फूहड़ भोजपुरी तथा हिन्दी गाने बिहार की स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों और महिलाओं का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं और वे नजरें झुकाकर सड़क पर चलने को मजबूर हैं।

इन्हीं गानों के चलते महिलाएं घर में टीवी भी देखना पसंद नहीं करती हैं। ऐसे गाना गाने वाले कई गायक आज प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं, जो समाज और देश के विकास में बाधक बन सकते हैं। जब लड़कियां या महिलाएं, सड़क पर सुरक्षित चल नहीं पायेंगी, तो क्या वे विकास के बारे में खाक सोच पायेंगी।

शराबी पतियों से महिलाओं को बचाने के लिए यदि कोई सरकार अपने राज्य में शराबबंदी का कानून ला सकती है तो क्या वह स्कूल-कॉलेज जाने वाली लड़कियों तथा महिलाओं के लिए इन फूहड़ गानों पर पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। मैं चाहती हूं कि बिहार में इन गानों के निर्माण और बजाने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

बिहार की बेटी नीतू चंद्रा श्रीवास्तव ने कहा कि फूहड़ गाने महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं तथा इन गानों का छोटे-छोटे बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ये गाने समाज को गलत दिशा में ले जा सकते हैं और महिलाओं के प्रति सम्मान को कम कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मैं तो बिहार के लोगों से इन गानों का पुरजोर विरोध करने की अपील करती हूं। उन्होंने कहा कि ऐसे गाना गाने वाले गायक और गायिकाओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिये। इन दिनों हनी सिंह का एक भोजपुरी गाना काफी वायरल हो रहा है, जो अश्लीलता के सारी सीमा तोड़े हुए हैं। भाषा का आड़ लेकर महिलाओं के शरीर पर किसी तरह की कमेंट नहीं होनी चाहिए फिर भोजपुरी भाषा को तो मैं देश-विदेश तक लेकर गयी हूं।

भोजपुरी भाषा में मैं सम्मान भी लेकर आयी हूं ऐसे में भोजपुरी भाषा के आड़ में कोई महिलाओं के लिए गंदे कमेंटस वाले गाने नहीं बर्दाश्त किया जा सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल किया गया है जिसकी अगुवाई सीनियर एडवोकेट निवेदिता निर्विकर ने विधिवत शशि प्रिया द्वारा सहायता किया जा रहा है। महिलाओं को कभी किसी को वस्तु समझने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि महिला का अपमान सदैव दुखदाई परिणाम का गवाह रहा है।

समारोह

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड बुधवार को मुंबई में भारतीय और बेल्जियम की कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान।

भरतपुर में राजपाल यादव की फिल्म 'चाय बिस्किट' की शूटिंग शुरू

भरतपुर/एजेन्सी

राजस्थान में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को नया आयाम मिलता दिख रहा है। मशहूर अभिनेता राजपाल यादव अपनी नई फिल्म 'चाय बिस्किट' की शूटिंग के लिए पहली बार भरतपुर पहुंचे। उन्होंने इसे सौभाग्य बताते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक शहर से उनका खास जुड़ाव है। फिल्म का निर्माण वॉक टू वे मीडिया द्वारा किया जा रहा है, जबकि निर्देशन की कमान सैफ और कौशल के हाथों में है। राजपाल यादव ने बताया कि यह सिनेमास्कोप फिल्म होगी, जिसे बेहद खास बनाने की कोशिश की जा रही है।

राजपाल यादव ने भरतपुर की सांस्कृतिक विरासत और महाराजा सूरजमल की वीरता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यह भूमि ब्रज क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिससे यहां अपनापन महसूस होता है।

'चाय बिस्किट' से जुड़ी खास बातें : फिल्म को संदीप कृष्णा प्रस्तुत कर रहे हैं। डायरेक्टर सैफ और कौशल के निर्देशन में यह खास फिल्म होगी। फिल्म का नाम निर्देशक की कल्पना का हिस्सा है। दर्शकों को एक नया और अनोखा अनुभव मिलेगा।

राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड से समन्वय बढ़ा रही है। इससे ऐतिहासिक शहरों को फिल्म इंडस्ट्री में नई पहचान मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। फिलहाल, राजपाल यादव अपनी टीम के साथ भरतपुर से रवाना हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने यहां बिताए गए समय को यादगार बताया। अब देखना दिलचस्प होगा कि 'चाय बिस्किट' दर्शकों को कितना पसंद आती है।

फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के पटियाला शैड्यूल की शूटिंग पूरी हुई

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की आने वाली फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के पटियाला शैड्यूल की शूटिंग पूरी हो गयी है। वर्ष 2019 में अजय देवगन,रकुल प्रीत सिंह और तब्बू की फिल्म 'दे दे प्यार दे' प्रदर्शित हुयी थी। इस फिल्म को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। अब इसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 बनाया जा रहा है। दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की मुख्य भूमिका है।रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म दे दे प्यार दे को लेकर अहम जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है।उन्होंने फिल्म दे दे प्यार दे 2 के पटियाला शेड्यूल के खत्म होने की खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की है और साथ ही एक खास नोट भी लिखा है।

रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म दे दे प्यार दे 2 को लेकर अपनी खुशी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर करते हुए एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके साथ क्रू के कई लोग नजर आ रहे हैं। इस खास तस्वीर के साथ रकुल ने लिखा, इसके साथ ही हमने दे दे प्यार दे 2 का पटियाला शेड्यूल पूरा कर लिया है। यह महीना बहुत अच्छा और संतोष देने वाला रहा। हां, ठंड बहुत थी और काम भी खूब था, लेकिन मेरी टीम ने मेरी मदद की और सब आसानी से हो गया। मैं चाहती हूं कि आप सब फिल्म देखें और उम्मीद है कि आपको आयशा का किरदार फिर से पसंद आएगा।

सम्मान

भाजपा नेता माधवी लता भारतीय पार्श्व गायिका और गीतकार पलक मुच्छल और अन्य गुरुवार को नई दिल्ली में अहिल्याबाई होल्कर महिला सम्मान समारोह भाग लेती हुई।

उन्हें सिर्फ नयनतारा कहें, लेडी सुपरस्टार नहीं : नयनतारा

चेन्नई/एजेन्सी

अभिनेत्री नयनतारा, जिन्हें उनके प्रशंसक अक्सर 'लेडी सुपरस्टार' के रूप में संबोधित करते हैं। उन्होंने अब मीडिया और दर्शकों से अपील की है कि वे अब से उन्हें सिर्फ नयनतारा के नाम से संबोधित करें, न कि लेडी सुपरस्टार के रूप में। मंगलवार देर रात एक बयान जारी करते नयनतारा ने कहा, एक अभिनेत्री के रूप में मेरी यात्रा के दौरान जो मुझे सफलता मिली और मुझे जो खुशी मिली मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। उन्होंने कहा, मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसे बिना किसी शर्त के प्यार और स्नेह से सजाया गया है। चाहे मेरी मेरी सफलता हो या फिर मुश्किल भरा दौर, मुझे सहारा देने के लिए आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे।

अभिनेत्री ने कहा कि कई लोगों ने उन्हें लेडी सुपरस्टार के नाम से पुकारा है, जो उनके अपार स्नेह की वजह से मिला नाम है। उन्होंने कहा, मुझे इस तरह के नाम से नवाजने के लिए मैं आप सभी की बहुत आभारी हूं। हालांकि, मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि मुझे 'नयनतारा' कहकर पुकारें। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि यह नाम मेरे दिल के सबसे करीब है। यह दर्शाता है कि मैं कौन हूं - न केवल एक अभिनेत्री के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी। अभिनेत्री ने यह भी बताया कि उपाधियां और प्रशंसाएं अमूल्य हैं, लेकिन वे कभी-कभी ऐसी छवि भी बना देती हैं, जो सितारों को उनके काम, उनकी कला और दर्शकों के साथ उनके बिना शर्त वाले बंधन से अलग कर देती हैं। मेरा मानना है कि हम सभी प्यार की भाषा साझा करते हैं, जो हमें सभी सीमाओं से परे जोड़े रखती है। मुझे बहुत खुशी है कि आपका अटूट समर्थन निरंतर बना रहेगा, और इसलिए आपका मनोरंजन करने के लिए मेरी कड़ी मेहनत भी जारी रहेगी। सिनेमा ही है जो हमें एकजुट रखता है, आइए हम इसे एक साथ मनाते रहें।

गोवा में महाराष्ट्र के लिए अविश्वसनीय नफरत : आयशा टाकिया

पणजी/भाषा। पूर्व अभिनेत्री आयशा टाकिया ने उनके पति व बेटे को सोमवार रात एक घटना के दौरान बुरी तरह परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस राज्य में ''महाराष्ट्र के लिए नफरत अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई है। गोवा पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आजमी के बेटे अबू फरहान आजमी और अन्य के खिलाफ राज्य में सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करने एवं शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया।

पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री टाकिया ने मंगलवार को 'इंस्टाग्राम स्टोरीज' पर एक पोस्ट में कहा कि उनके पति ने मदद के लिए पुलिस को बुलाया था, लेकिन उनके खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर दी गई। टाकिया ने कहा, हमारे परिवार के लिए यह रात एक भयावह रात थी... अभी-अभी यह पोस्ट देखा और इसे साझा करना ज़रूरी है।

मैं समय आने पर और भी चीजें साझा करूंगी... मेरे पति और बेटे को बुरी तरह से धमकाया गया और वे अपनी जान को लेकर डरे हुए थे क्योंकि गोवा के स्थानीय गुंडों ने उन्हें घेर लिया, उन्हें धमकाया और घंटों तक प्रताड़ित किया...उन्होंने पुलिस के साथ भी बुरी तरह मारपीट की, जिसे मेरे पति ने हमारे बेटे और अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा, गोवा में महाराष्ट्र के प्रति नफरत

अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई है... वे फरहान और मेरे बेटे को महाराष्ट्र से होने और बड़ी कार रखने के लिए बार-बार अपशब्द कहते रहे।

टाकिया ने कहा, पुलिस ने फरहान के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर ली है, जबकि वास्तव में उन्होंने ही लगभग 150 लोगों की भीड़ के खिलाफ मदद के लिए 100 नंबर डायल किया था। उन्होंने एक अन्य 'इंस्टाग्राम स्टोरीज' पर लिखा कि परिवार के पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित ''वीडियो सबूत'' हैं, जिन्हें वे समय आने पर सक्षम अधिकारियों के साथ साझा करेंगे। गोवा पुलिस ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि उनके नियंत्रण कक्ष को सोमवार रात 11.12 बजे एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि (उत्तरी गोवा जिला) कैंडोलिम में एक सुपरमार्केट में झगड़ा हो रहा है। कलंगुट पुलिस के निरीक्षक परेश नाइक ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि झगड़े के दौरान अबू फरहान आज़मी ने प्रतिद्वंद्वी समूह से कहा था कि उसके पास लाइसेंसी हथियार है। अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि फरहान आजमी के समूह सहित दो समूहों के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि अबू फरहान आज़मी, ज़ियोन फर्नांडीस, जोसेफ फर्नांडीस, शाम और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
www.dakshinbharat.com
epaper.dakshinbharat.com
बेंगलूरु | शुक्रवार | 07-03-2025 /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY
RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2018-2020
Posted at Bengaluru PSO
Mysore Road Bengaluru-560 026.

बेंगलूरु की ओर विहाररत आचार्यश्री विमलसागरसूरीश्वरजी ने आदिचुनचनगिरि मठ में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए जैनाचार्य ने कहा कि मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार नहीं, परिणामों को देखकर चलना चाहिए।

निमंत्रण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के जैन युवा संगठन के अध्यक्ष महावीर मुणोत के नेतृत्व में उपाध्यक्ष मुकेश सुराणा, अतिथि आमंत्रण समिति चेयरमैन मोती गोटावत, सह चेयरमैन दीपक धोका, मनोज गुंदेचा, कार्यकारिणी समिति सदस्य आतिश धोका, रितेश पामेचा, शैलेन्द्र मोगरा, दीपेश धोका ने कर्नाटक के शहरी ग्रामीण विकास मंत्री बैराती सुरेश से मुलाकात कर 10 अप्रैल को फ्रीडम पार्क में आयोजित हो रहे 2624वें प्रभु महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण देकर निवेदन किया।

आचार्यश्री अभयशेखरसूरी का कल होगा प्रवेश

बेंगलूरु। शहर के शांतिनगर जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ के तत्वावधान में प्रेम-भुवनभानुसूरी समुदाय के आचार्यश्री अभयशेखरसूरीश्वरजी अपने 40 सहयोगी साधु साध्वियों के साथ पहली बार शांतिनगर आ रहे हैं। शनिवार को एंड्री रोड में महेन्द्रकुमार बालिया के निवास पर संतों का पदार्पण व पगलिया होगा।

उसके बाद संघ के साथ शोभायात्रा के रूप में आचार्यश्री विभिन्न मार्गों से होते हुए आदिनाथ जैन मंदिर में परमात्मा के दर्शन करते हुए लुणावत जैन स्थानक हॉल पहुंचेंगे, जहां सुबह 9 बजे उनका प्रवचन होगा। लुणावत जैन स्थानक में सभी संत विराजमान होंगे।

आपसी विवाद है प्रगति में सबसे बड़ी बाधा : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हिरियूर। बेंगलूरु की ओर विहाररत आचार्यश्री विमलसागरसूरीश्वरजी ने आदिचुनचनगिरि मठ में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए जैनाचार्य ने कहा कि मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार नहीं, परिणामों को देखकर चलना चाहिए। परिस्थितियां जीवन को जितना प्रभावित नहीं करतीं, उतने परिणाम असरकारक या खतरनाक हो सकते हैं। किसी भी बात को लेकर कोई विवाद कभी भी आकार ले सकता है। आसपास के समझदार लोग विवाद की उस अग्नि को विकराल होने से बचा सकते हैं। मनुष्य के बुद्धिमान होने की यही परीक्षा है। जो लोग विवादों के अग्निकुंड में आहुतियां देकर खुश होते हैं वे किसी अपराधी से कम नहीं माने जा सकते। यह गहन पापप्रद

मानसिकता है। जब ऐसे लोगों के जीवन में कभी विवाद होते हैं तो दुनिया उसका मुफ्त में तमाशा देखती है। ऐसे लोगों को बचाने कोई नहीं आता।

आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि परस्पर संवाद और तालमेल प्रगति का मूलमंत्र है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम विवादों को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। राष्ट्र, प्रान्त, धर्म, समाज, संगठन, व्यापार और परिवार, सभी क्षेत्रों में आपसी विवाद प्रगति को अवरुद्ध करते हैं और उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं को क्षीण बनाते हैं। विवादों से कोई विशेष लाभ नहीं होता। उन्हें टालना मनुष्य की बुद्धिमानी है। व्यक्ति का अहंकार अथवा उसकी जिद्द विवाद की पैदाइश और बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुद्धि की वक्रता और जड़ता किसी भी बात, घटना और परिस्थिति के विविध आयामों को समझने में निष्फल रहती है। विवाद के परिणाम दुःखदायी होते हैं और उसकी चरम सीमा विनाश लाती है। प्रयत्न पूर्वक सरलता और समझदारी से विवादों को सुलझाया जा सकता है। गणि पद्मविमलसागरजी ने भी अपने विचार प्रकट किए।

बैठक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के आऊवा महिला मंडल की मासिक संगोष्ठी बसवनगुड़ी स्थित जयश्री रायसोनी के निवास स्थान पर हुई जिसमें अध्यक्ष कांता रायसोनी ने सभी का स्वागत किया और होली त्यौहार की शुभकामनाएँ दी। महिला दिवस' विषय पर आयोजित बैठक में प्रमुख वक्ता बिंदु रायसोनी ने कहा कि हर नारी में अनेक रंग समाए हुए होते हैं। हर रंग किसी न किसी विशेषता का प्रतीक होता है। जिस प्रकार लाल रंग शौर्य का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग शांति का प्रतीक है। नारी हर असंभव काम को संभव करने की क्षमता रखती है। कांता रायसोनी ने संचालन किया।

राजस्थान के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। दक्षिण पश्चिम रेलवे बेंगलूरु मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति (डीआरयूसीसी) के सदस्य अश्विन सेमलानी ने राजस्थानी प्रवासियों की ओर से गुरुवार को बेंगलूरु मंडल रेल प्रबंधक अमितेशकुमार सिन्हा से शिष्टाचार भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बेंगलूरु से अजमेर के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 16209/16210 का ठहराव पाली जिले के जवाईबांध स्टेशन पर सुनिश्चित कराने, बेंगलूरु से भीलड़ी-जालोर मार्ग पर वाया हुब्बल्ली, पुणे चलने वाली ट्रेन संख्या 14805/06 को साप्ताहिक से सप्ताह में तीन बार चलाने, बेंगलूरु से जोधपुर वाया भीलड़ी-जालोर एक अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाने की मांग की है। अश्विन ने बताया कि लगभग 20 लाख से अधिक राजस्थानी प्रवासी व्यवसाय, उद्योग, धंधे व नौकरी के सिलसिले में समूचे कर्नाटक में रहते हैं, उनकी सुविधा व सहूलियत के लिए यह मांगें की जा रही हैं।

उत्साहवर्धन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के राजाजीनगर फाइटर एवं कर्नाटक रक्षण वेदिके के संयुक्त तत्वावधान में राजाजीनगर राममंदिर खेल मैदान में क्रिकेट स्पर्धा चैलेंज कप' का आयोजन किया गया जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित महेंद्र मुणोत ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुणोत ने कहा कि हर खिलाड़ी को खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए ताकि भाईचारे में बढ़ावा हो।

सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के अग्रवाल समाज कर्नाटक के अध्यक्ष सुभाष बंसल, सचिव सतीश गोयल, विक्रम अग्रवाल, रोहित केडिया, वरिष्ठ सदस्य बिपिनराम अग्रवाल आदि ने बेंगलूरु प्रवास पर आए कुरुक्षेत्र ब्रह्मपुरी अन्नक्षेत्र आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत 18 मंजिला ज्ञान मंदिर के संचालक स्वामी चिरंजीवपुरीजी महाराज का समाज कार्यालय में सम्मान किया।इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद व ट्रस्ट के अध्यक्ष सुशील गुप्ता व अध्यक्ष राजेश गोयल का भी सम्मान किया गया।

ऐसे समाज की जरूरत, जहां किसी को भी लिंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव महसूस न हो: गडकरी

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां किसी को भी लिंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव महसूस न हो।

गडकरी ने आठ मार्च को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले समाज में असामान्य योगदान देने वाली महिलाओं को 'लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर महिला सम्मान' प्रदान करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की।

गडकरी ने कहा, ''हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां किसी को जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं आंका जाए, बल्कि उनकी प्रतिभा और योगदान के आधार पर आंका जाए।''

यह पुरस्कार मुंबई स्थित कमला अंकीबाई घमंडीराम गोवानी ट्रस्ट प्रदान करता है।

गडकरी ने कहा कि दुनिया अब बदल गई है और महिलाओं को

अपने लिंग के आधार पर सीमित महसूस नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''जहां योग्यता मौजूद है, वहां महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों में 75 प्रतिशत महिलाएं हैं।''

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिला सशक्तीकरण और पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा द्वारा इस संबंध में की गई प्रगति के बारे में बात की। उन्होंने याद किया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने महिलाओं के संबंध में राज्य में व्याप्त गहरी वर्जनाओं को देखा।

खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पहल हरियाणा में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, राज्य में महिलाओं के लिए समर्पित 30 पुलिस थाने स्थापित किए गए थे और इन सभी थानों का प्रबंधन महिला अधिकारियों द्वारा किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी परेशानियों को आसानी से प्रस्तुत कर सकें।

'खाकी' के प्रोमो में पुलिस की वर्दी में दिखे सौरव गांगुली, ओटीटी सीरीज में अभिनय की अटकलें तेज

कोलकाता/भाषा। नीरज पांडे की आगामी नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर, 'खाकी: द बंगाल चैप्टर' के एक प्रमोशनल विज्ञापन शूट में क्रिकेट सौरव गांगुली की उपस्थिति ने ओटीटी सीरिज में उनकी संभावित भूमिका के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, इसके निर्माता ने स्थिति स्पष्ट नहीं किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या गांगुली इस शृंखला में अतिथि भूमिका में होंगे, पांडे ने मुसकुराते हुए कहा, ''जहां तक सौरव का सवाल है...खैर, देखते रहिए।''

पांडे ने हालांकि इस बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन निर्माण टीम से जुड़े एक सूत्र ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि फिलहाल गांगुली के सीरीज में अभिनय की शुरुआत करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यहां तक कि मेहमान भूमिका के बारे में भी।

सूत्र ने बताया, ''वह बारुईपुर में शूट किए गए एक प्रमोशनल वीडियो में नजर आए।''

शूटिंग के दौरान पुलिस वर्दी में गांगुली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद अटकलें तेज हो गईं।

आगामी थ्रिलर 2000 के दशक के आरंभिक कोलकाता की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां एक आईपीएस अधिकारी शहर के अपराध सिंडिकेट से लड़ता है और उसके काले पहलुओं को उजागर करता है ओटीटी पर सीरिज के प्रीमियर से पहले प्रचार वीडियो जारी किए जाएंगे। 'खाकी: द बंगाल चैप्टर' पांडे की खाकी शृंखला की दूसरी किस्त है जो 20 मार्च को प्रसारित करने के लिए तैयार है।इससे पहले 'खाकी: द बिहार चैप्टर' का प्रसारण 2022 में ओटीटी पर हुआ था।

'वेकिंग ऑफ ए नेशन' सीरीज़ में जलियांवाला बाग हत्याकांड को संवेदनशीलता से लिया गया: राम माधवानी

मुंबई/भाषा। फिल्म निर्माता राम माधवानी का कहना है कि उन्होंने अपनी आगामी सीरीज़ वेकिंग ऑफ ए नेशन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की मार्मिक ऐतिहासिक घटनाओं में से एक, जलियांवाला बाग हत्याकांड को संवेदनशील और ईमानदार तरीके से दिखाने का प्रयास किया है।

औपनिवेशिक शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित यह ऐतिहासिक सीरीज़ जलियांवाला बाग हत्याकांड की साजिश और उससे जुड़ी घटनाओं तथा इस त्रासदी के संबंध में हंटर आयोग की जांच पर आधारित है।

वेकिंग ऑफ ए नेशन का सह-लेखन माधवानी, शांतनु श्रीवास्तव और शत्रुजीत नाथ ने किया है। माधवानी ने कहा कि वह इस सीरीज़ के जरिए उन लोगों की स्मृतियों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' के साथ साक्षात्कार में कहा, हमने नरसंहार नहीं दिखाया है, हमने सिर्फ सैनिकों को आते हुए दिखाया है। मैं इसे नहीं दिखाना चाहता था, और जिस तरह से हमने इसे दिखाया, उसमें यही सबसे संवेदनशील हिस्सा था। दूसरे फिल्म निर्माताओं ने नरसंहार दिखाया है। हम नहीं जानते कि 400 लोग मारे गए थे या 2,000..., इसलिए इसे न दिखाना ज़्यादा सम्मानजनक होगा।

एमी पुरस्कार विजेता निर्देशक ने कहा, हमने इसे उन लोगों को समर्पित किया है जिन्होंने नरसंहार के दौरान अपनी जान गंवाई है, और हम इसे अत्यंत सम्मान और संवेदनशीलता के साथ पेश करना चाहते थे। फिल्म निर्माता ने यह भी कहा कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में अंग्रेजों के व्यंग्यात्मक चित्रण से भी दूर रहने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने खलनायकी का काम किया है, लेकिन वे सोच रहे थे कि वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्हें खलनायक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन किसी नाटकीय तरीके से नहीं।

वेकिंग ऑफ ए नेशन के निर्माता राम माधवानी और उनकी पत्नी हैं और इसका प्रसारण सात मार्च मार्च को 'सोनी लिव' पर होगा। इसकी कहानी चार मित्रों : एक वकील कांतिलाल साहनी (तारुक रैना), एक पत्रकार अली अल्लाबख्श (साहिल मेहता), एक आम आदमी हरि सिंह (भवशील सिंह) और उसकी पत्नी पूनम (निकिता दत्ता) के नजरिये से बताने का प्रयास किया गया है। सीरीज में ब्रिटिश कलाकारों पॉल मैक्ईवान और एलेक्स रीस ने भी काम किया है।

कैट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेडे का मुंबई से चेन्नई स्थानांतरण रद्द किया

नयी दिल्ली। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेडे का मुंबई से चेन्नई तबादला यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राजस्व विभाग ने अपने स्वयं के तबादला दिशानिर्देशों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया है। वर्ष 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेडे 2021 में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई में अपने कार्यकाल के दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के परिवार से उनके बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले में कथित तौर पर फंसाने की धमकी देकर 25 करोड़ रुपये की मांग को लेकर सुर्खियों में आये थे। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और सदस्य राजिंदर कश्यप की कैट की मुख्य पीठ ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्थानांतरण निर्णय में प्रक्रियात्मक खामियां और संभावित पूर्वाग्रह पाया। अधिकरण ने कहा कि हालांकि सरकारी अधिकारियों का अखिल भारतीय सेवा दायित्व होता है, लेकिन स्थानांतरण नीतियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

कैट के 20 फरवरी के आदेश में कहा गया है, हम इस तथ्य से भली-भांति अवगत हैं कि यह एक स्थापित कानून है कि स्थानांतरण, जो सेवा का हिस्सा है, में अदालतों द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना या दुर्भावनापूर्ण या स्थानांतरण को नियंत्रित करने वाले किसी भी घोषित मानदंड या सिद्धांत के उल्लंघन से प्रभावित न हो। हालांकि, प्रतिवादियों का कदम ऐसा है जो उनके द्वारा निर्धारित नीतिगत ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है।

पीठ ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा उद्धृत निर्णय उसका बचाव नहीं करेंगे, क्योंकि उसने वानखेडे को स्थानांतरित करते समय दिशानिर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया था।

प्रश्नपत्र लीक मामला: यूट्यूब चैनल मालिक को अग्रिम जमानत देने से अदालत का इनकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने 11वीं कक्षा के परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने केरल पुलिस की अपराध शाखा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने आरोपी शुहैब की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत बताई है। अदालत ने उसे जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, शुहैब ने कोझिकोड में अपराध शाखा कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां उसने संवाददाताओं से कहा कि उसे और उसके यूट्यूब चैनल एम एस सॉल्यूशंस को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

शुहैब ने आरोप लगाया कि एक बड़े मंच ने उसके और उसके चैनल के खिलाफ साजिश रची है। उच्च न्यायालय ने शुहैब को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया कि परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जानी चाहिए तथा प्रश्नपत्रों का लीक होना उन छात्रों के खिलाफ धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला होगा, जिन्होंने परीक्षा के लिए लगन से तैयारी की होती है। इसने कहा, इसलिए, शिक्षा प्रणाली में परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखा जाना चाहिए। प्रश्नपत्र लीक होने से परीक्षा प्रक्रिया, अभ्यर्थियों और शिक्षा विभाग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इससे विभाग की विश्वसनीयता को क्षति हो सकती है, छात्रों में चिंता और तनाव उत्पन्न हो सकता है और लीक हुए पेपर तक पहुंच रखने वालों को अनुचित लाभ मिल सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने विस्तृत जांच की मांग की, जिसके लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।

बधाई

केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री और झारखंड भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को रांची में झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुने जाने पर झारखंड भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बधाई दी।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com